प्रस्तावना

महात्मा गांधी जी का राजनीतिक व आर्थिक विचारों के साथ-साथ सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी उनके विचारों और कार्यो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दक्षिण अफ्रीका से भारत में आकर भी उन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में यहाँ पर प्रचलित अन्याय, अत्याचार व उत्पीडन का घोर विरोध करते हुए उसके खिलाफ कडा संघर्ष किया। गांधी जी ने दलितों की मुक्ति के लिए जो कठिन प्रयास किए उससे यह स्पष्ट होता है कि उनका सामाजिक न्याय के साथ गहरा लगाव रहा था। इन सभी कार्यो में उनके साथ साये के रूप में कस्तुरबा जी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष महात्मा गांधी जी और कस्तुरबा गांधी जी की 150 वीं जयंती वर्ष बा-बापू 150वीं के नाम से पूरे देश और दुनिया में मनायी जा रही है।

पूज्य बापू के सिद्वांत अहिंसा, सत्य, प्रेम, मानवता, भाईचारा, विश्वबंधुत्व, स्वावलम्बन, ग्राम स्वराज्य, समानता, सामूहिकता और न्याय को धरा पर उतारने के लिए महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा विगत 48 वर्षो से चम्बल घाटी, मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। आश्रम के द्वारा वर्ष 2018-19 के कार्यो पर आधारित यह वार्षिक प्रगति पुस्तिका आपके लिए प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस वर्ष महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्था को 'श्री विष्णु कुमार महिला बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान' पुरस्कार प्राप्त हुआ।

चम्बल घाटी में बागी आत्मसमर्पण की ऐतिहासिक घटना 'हिंसा पर अहिंसा का विजय' के 45 वर्ष पूरे हो गये हैं। चम्बल घाटी अनवरत पूरे देश एंव दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश प्रचारित कर रही है। समाज में ढांचागत हिंसा के समूल नाश के लिए शोषण, अन्याय और अत्याचार तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज की रचना के लिए संस्था ने बड़े पैमाने पर काम किया है।

संस्था की खादी ग्रामोद्योग इकाई के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर खादी सुधार विकास कार्यक्रम के माध्यम से खादी के उत्पादन एवं विक्री को नई ऊंचाइयां हासिल की गयी है। इसके माध्यम से हजारों विकलांग रोजगार विहीन महिलाओं तथा पुरुषों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है वहीं दूसरी ओर खादी की बुनाई के काम में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। चंबल घाटी में मधुमक्खी पालन की संभावनाओं को विस्तार देते हुए हजारों लोगों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देने के बाद मधुमक्खी पालन के रोजगार से जोड़ा गया है जिसमें अंचल की 500 से अधिक गरीब और वंचित समुदाय की महिलाओं की मधुमक्खी पालन में भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिससे वे आर्थिक रूप से स्वाबलम्बी होकर गरिमामय जीवन जी रही हैं।

चंबल घाटी सरसों के उत्पादन के लिए काफी विख्यात है यहां की उत्पादित सरसों बाहर भेज दी जाती है और इस अंचल में लोगों को सरसों का शुद्ध तेल उपलब्ध नहीं हो पाता। इस वर्ष गांधी आश्रम ने परांपरागत और आधुनिक तेल इकाई की स्थापना कर जैविक सरसों के बीज से शुद्व सरसों के तेल का उत्पादन शुरू किया है। इससे एक तरफ दर्जनों किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल रहा है तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को शुद्ध सरसों का तेल उपलब्ध हो रहा है। अंचल के युवक-युवतियों में कौशल विकास के लिए 25 कंप्यूटरों के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन प्रारंभ किया गया है। जहां पर कंप्यूटर के बेसिक कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वे अपने हुनर को विकसित कर रोजगार प्राप्त कर सकें।

कुपोषण के कारण बदनाम श्योपुर में कुपोषण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अभियान के माध्यम से श्योपुर जिले की 1227 आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रशिक्षण देकर 80000 से अधिक 15 से 45 वर्ष के बीच की महिलाओं की भागीदारी से कुपोषण मुक्त अभियान प्रारंभ किया गया। इसके सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं और कुपोषण का स्तर सुपोषण में बदलता जा रहा है। पोषण बाड़ी निर्माण और विकास का जो प्रयोग संस्था के द्वारा प्रारभ किया गया है उसकी सफलता से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण वाड़ी कार्यक्रम को अभियान के तौर पर लिया है। इस अभियान के तहत 15 वर्ष से 49 वर्ष की सभी महिलाओं को अपने परिवार को कुपोषण से मुक्त करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही 50 गांव में खेती आधारित टिकाऊ आजीविका को विकसित करने का कार्य किया जाएगा जिसमें कम पानी की खेती में पोषण युक्त फसल की पैदावार तथा 5000 से अधिक परिवारों में पोषण बाड़ी विकसित की जाएगी जिससे प्रत्येक परिवार को पूरे वर्ष भर हरी सब्जियां मिल सके और परिवार कुपोषण के दायरे से बाहर आ सके। इसमें शुद्ध पीने का पानी, स्वच्छता एवं साफ सफाई, खेत स्कूल, वर्मी कंपोस्ट तथा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी काम किया जाएगा।

अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के विकास को मापने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें श्योपुर जिले के कराहल विकासखंड के लगभग 30,000 बच्चों का सर्वे किया जाएगा तथा आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उनके शारीरिक विकास की मानिटरिंग की जाएगी जिससे कि कुपोषित बच्चों का समय से उपचार किया जा सके और कुपोषण में जाने से पहले ही उनको बचाया जा सके। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषित पाये गये हैं, यूनिसेफ की मदद से इस जिले में श्योपुर की तरह कुपोषण के विरूद्ध अभियान शुरू किया गया है।

श्योपुर जिले में बालिकाओं की शिक्षा की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आश्रम के द्वारा बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत उन सभी बालिकाओं जो किसी कारण से स्कूल जाने से वंचित रह गई है अथवा पढ़ाई छोड़ दी हैं उनकी पहचान और शिक्षा के लिए 90 अनौपचारिक शिक्षा केंद्र प्रारंभ किया गया हैं। इसमें 2700 बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही है जिनको 5 साल तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में जो बालिकाएं पांचवीं की बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेगीं उनको शासकीय स्कूलों में दाखिला कराया जायेगा। जिससे कि शिक्षा से वंचित सभी बालिकाओं को मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके।

बच्चों के अधिकार के लिए चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन भारत सरकार की मदद से श्योपुर में संस्था के द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन में अभी तक 25000 बालक बालिकाओं को सहायता उपलब्ध करायी गयी है। किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा एवं अन्याय से जूझ रहे बच्चों को सहायता उपलब्ध कराना तथा उनको खतरे से बाहर निकालने का काम चाइल्डलाइन के द्वारा किया जा रहा है।

जल जंगल जमीन पर लोगों के अधिकार की मुहिम लगातार चल रही है। अभी भी जिन लोगों को भूमि का अधिकार नहीं मिला है उनको अधिकार दिलाने और उनके जमीन के विकास एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे देश में भूमि आधारित आजीविका की स्थापना के लिए प्रयास संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले में कपास की खेती में शामिल बच्चों की पहचान कर उनके बाल अधिकारों तक पहुंच बनाने में शिक्षा और स्वावलम्बन के कार्य को किया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में

बालिकाओं को स्वच्छता एवं साफ सफाई तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संस्था के द्वारा प्रदेश के 6 जिलों में 1200 बालिकाओं के बीच कार्य किया जा रहा है।

मुझे उम्मीद है कि महात्मा गांधी के विचार और सिद्धांतों को धरातल पर उतारने का कार्य संस्था द्वारा अनवरत जारी रहेगा। महात्मा गांधी सेवा आश्रम के अध्यक्ष डॉ. एस.एन. सुब्बराव जी के विचारों को आश्रम के उपाध्यक्ष श्री पी. वी. राजगोपाल ने रचनात्मक दिशा प्रदान की है। कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य श्री सत्यवान जी चौहान के द्वारा श्योपुर की सभी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी एवं मार्गदर्शन कार्यो को परिणाम तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण रहा है। वरिष्ठ सदस्य श्री महेश दत्त मिश्र के निंरतर मार्गदर्शन और सानिध्य में जौरा केन्द्र रचनात्मक कार्यो को को आगे बढ़ा रहा है। संस्था के कोषाध्यक्ष श्री परशुराम सिंह सिकरवार जी सक्रियता और सहज उपलब्धता कार्यो को पूरे अंचल में फैलाने में सहयोग प्रदान करती है। हमारे वयोवृद्ध सदस्य श्री गुलजारीलाल जैन उम्र के बावजूद भी लगातार आश्रम की गतिविधियों के साथ जुड़े रहते है। खादी के विकास में जगदीश सिंह जी एवं आदिवासियों के अधिकारों के लिए मदद करने वाली साबो बाई सहित सभी सम्मानित सदस्यों के सहयोग से ही संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संस्था के कार्या से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति में आदर और सम्मान व्यक्त करता हूँ।

साभार

(रनसिंह परमार)
सचिव,

अनुक्रमणिका

क्रं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	आर्थिक सशक्तिकरण के लिये खादी एवं ग्रामोद्योग आधारित आजीविका का सृजन	
	• खादी उत्पादन	10
	• खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम	12
	• शहद उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन	13
	• केंचुआ खाद	14
2.	"कुपोषण से मुक्ति अभियान" में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधिता कार्यक्रम	16
3.	बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ कार्यक्रम श्योपुर	21
4.	चाइल्डलाइन के माध्यम से आपातकालीन पहुंच सेवा - श्योपुर	24
5.	कस्तुरवा गांधी छात्रावास की बालिकाओं में जल स्वछता एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार परिवर्तन।	27
6.	"सहभागी सीख प्रक्रिया" से कुपोषण मुक्ति अभियान जिला-बड़वानी	30
7.	वंचित समुदाय का सशक्तिकरण	32
8.	मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के वंचित समुदाय के लिए टिकाउपन आजीविका सुनिश्चित करना	38
9.	Regional Nutrition Program - Sheopur (M.P.)	42
10.	"TRAPPED IN COTTON" PROJECT, DHAR (M. P.)	49
11.	BUILDING DOMESTIC RESOURCE MOBILIZATION CAPACITIES OF CSO'STHROUGH INNOVATION TECHNOLOGY & SOCIAL ENTERPRISE54	

डा. एस.एन. सुब्बराव (भाईजी)

भाई जी के प्रिय संबोधन से देश दुनिया में लाखों लोगों के प्रेरणा स्त्रोत डा. एस.एन. सुब्बाराव में लोग आज के विषम दौर में भी गांधीवाद की एक नई संकल्पना का साक्षात्कार करते हैं। सत्य व न्याय आधारित शांतिमय विश्व की स्थापना के लिये आजीवन समर्पित भाई जी को 1942 में मात्र 13 वर्ष की अवस्था में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल यात्रा करनी पड़ी।

बैंगलोर में पैदा हुये भाई जी, बचपन में ही रामकृष्ण परम हंस, स्वामी विवेकानंद, और महात्मा गांधी से प्रभावित हुये। आजादी की लड़ाई के दौरान देश के जाने माने नेता डा. एन.एस. हार्डिकर के नेतृत्व में हिन्दुस्तानी सेवा दल के माध्यम से युवा प्रशिक्षणों की एक श्रंखला चलाई।

कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के आग्रह पर घर परिवार के माया मोह से मुक्त हो भाई जी कांग्रेस सेवादल के माध्यम से राष्ट्र निर्माण अभियान में लग गये। संविधान में सूचीबद्ध सभी भाषाओं के ज्ञाता और गीत संगीत, सर्वधर्म प्रार्थना द्वारा लोगों को प्रेरित करने वाले भाई जी ने 1951 से 1969 तक कांग्रेस सेवादल के माध्यम से देश सेवा की। पं. नेहरु, आर.आर. दिवाकर, मौलाना आजाद, के. कामराज, लाल बहादुर शास्त्री के सन्निकट रहकर भी सत्ता के बजाय सेवा की राजनीति में कूदे और शांति स्थापना में जुट गये।

गांधी शांति प्रतिष्ठान के आजीवन सदस्य रहे भाई जी ने उस दौर के सर्वाधिक हिंसाग्रस्त चंम्बल घाटी को अपना घर बनाया और 1970 में महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा की स्थापना कर बिनोभा, जयप्रकाश नारायण का हिंसा मुक्ति का सपना 1972 - 1976 में 654 बागियों का समर्पण कराकर पूरा किया।

1947 में देश की आजादी के उपरांत भारत की अहिंसक क्रांति की दूसरी बड़ी ऐतिहासिक घटना को अंजाम देने वाले भाई जी ने राष्ट्रीय युवा योजना की स्थापना कर युवा शिविरों के माध्यम से देश दुनिया के लाखों नौजवानों को प्रशिक्षित कर रचनात्मक आंदोलन की एक नई पृष्ठभूमि तैयार की।

राष्ट्रीय, लोकतांत्रिक, मानवीय, विश्वशांति, सत्याग्रह जैसे वैश्विक मूल्यों को धरातल पर जीवन्तता प्रदान करने वाले भाई जी के प्रयासों नें पूरे देश में एक नई जाग्रति पैदा की है। इण्डियन मर्चेंट चेम्बर मुम्बई, जमनालाल बजाज पुरुस्कार, राजीवगांधी राष्ट्रीय सदभावना पुरुस्कार, इन्दिरा गांधी सेवा पुरुस्कार, सुलभ सम्मान, डी. लिट. काशी विद्यापीठ वाराणसी से सम्मानित भाई जी का व्यक्तित्व और कृतित्व शांति एवं समता युक्त मानवीय समाज के लिये स्वयं एक नैसर्गिक पुरुस्कार हैं।

गांधीवादी जनसंगठन एकता परिषद के प्रेरणा स्रोत, गांधी भवन न्यास भोपाल के अध्यक्ष, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य, नेहरु युवा केन्द्र बोर्ड के सदस्य होने के साथ साथ सर्व सेवा संघ, कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, सेवाग्राम आश्रम जैसे गांधी वादी संस्थाओं के साथ भी भाई जी सक्रियता से जुड़कर कार्य कर रहे हैं।

महात्मा गांधी सेवा आश्रम

महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना विषम परिस्थितियों में हुई थी जब संपूर्ण चंबल घाटी हिंसा की चपेट में थी तथा नौजवान शासन और समाज के द्वारा किए गए अन्याय के विरोध में बंदूक उठाकर चंबल के बीहड़ों में समा रहे थे। यह वही युवा थे जिन्होंने एक समय आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का साथ दिया था, जो अंग्रेजो के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके लिए गोला बारूद, खाना एवं रुकने की जगह उपलब्ध कराने का काम चंबल घाटी के इन बागियों ने किया था साथ ही जब जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ बदला लेने की नीयत से योजना बनाते थे तो उस योजना को अंजाम देने का काम चंबल घाटी के द्वारा किया जाता था। चंबल घाटी के युवाओं ने महान गांधीवादी श्री सुब्बाराव जी से निवेदन किया था कि चंबल घाटी हिंसा की चपेट में है तथा नौजवान अपने हाथों में हथियार उठा रहे हैं, कृपया इन नौजवानों को शांति के रास्ते पर लाने के लिए कुछ प्रयास करे।

इसके पश्चात परम आदरणीय भाई जी ने चंबल अंचल की तरफ रुख किया और यहां युवा शिविरों की श्रंखला शुरू की। इन शांति के प्रयासों में युवा शिविरों का आयोजन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। इन शिविरों ने एक तरफ चंबल घाटी के नौजवानों में श्रम संस्कार के बीज बोने का काम किया तो दूसरी तरफ चंबल घाटी में और संपूर्ण समाज में शांति स्थापित करने की दिशा में इस अंचल के नौजवानों को प्रेरित किया । इसी का परिणाम यह हुआ कि चंबल घाटी के बागी, भाई जी की प्रेरणा से तथा महात्मा गांधी के सिद्धांतों से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों के सामने हथियार डालने का मन बनाया। उसी समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण पूरे देश में शांति और अहिंसा की मिसाल लेकर न्याय पर आधारित समाज की रचना के लिए देश की तरुणाई को प्रेरित करने का काम कर रहे थे । जब पूज्यनीय लोकनायक के सामने चंबल घाटी की हिंसा की समस्या को रखा गया तथा यह भी समझाया गया चंबल घाटी के बागी जिन्होंने अन्याय के खिलाफ हथियार उठाए थे वह महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। लोक नायक जी समय दे दे । चंबल घाटी के सभी बागी महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने हथियार रखने के लिए तैयार हैं ।

इस प्रकार का प्रस्ताव सुनकर स्व. श्री लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने हां कर दी और फिर 14 अप्रैल 1972 को चंबल घाटी के छैरा नामक स्थान पर महात्मा गांधी सेवा आश्रम के परिसर में ऐतिहासिक बागी आत्मसमर्पण का प्रारंभ हुआ जिसमें कुल मिलाकर 654 बागियों ने गांधीजी के रास्ते हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और सद्भाव के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया ।

चंबल घाटी में शांति और अहिंसा के मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना हुई थी उसमें यह एक बड़ी जीत थी। चंबल घाटी के बागी अपने हथियार गांधी जी की मूर्ति के सामने सौंप कर जेल में चले गए लेकिन फिर भी समाज अन्याय और शोषण से मुक्त नहीं हुआ, इसलिए महात्मा गांधी सेवा आश्रम की जवाबदेही और बढ़ी और गांधी आश्रम के द्वारा चंबल घाटी में शांति के प्रयासों के साथ साथ रचनात्मक कामों की शुरुआत की गई ।

पीने के लिए पानी हो या आजीविका के लिए जल जंगल जमीन पर लोगों का अधिकार हो या बेरोजगार लोगों के हाथों को रोजगार मुहैया कराने का कार्यक्रम हो, हर क्षेत्र में महात्मा गांधी सेवा आश्रम ने अलग प्रकार के काम हाथ में लिए और इस क्षेत्र की तरुणाई को रचनात्मक कामों के साथ जोड़ने का काम किया।

चंबल घाटी में शांति के प्रयासों की श्रृंखला में भाई जी के नेतृत्व में 47 राष्ट्रीय युवा नेतृत्व शिविरों का आयोजन किया गया जिन्होंने चंबल घाटी के दूरदराज गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया इतने बड़े पैमाने पर श्रमदान के माध्यम से 47 गांव मुख्य मार्ग से जुड़े उसका परिणाम यह हुआ कि सामूहिक श्रम के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा तथा समाज सेवा के प्रति भी बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे।

महात्मा गांधी सेवा आश्रम ने खादी और ग्रामोद्योग, पीने के लिए शुद्ध पानी, साक्षरता अभियान, सिंचाई के लिए पानी रोकने का काम, संरक्षण संवर्धन के लिए छोटे–छोटे बांध बनाने का काम, तथा चंबल घाटी की कृषि उन्नति का काम एवं ग्रामीण उद्योगों को स्थापित करने का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया । जिसके परिणाम स्वरूप इस अंचल के युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में आश्रम के साथ जुड़ी । इसके अलावा अन्याय व अत्याचार मुक्त समाज की स्थापना के लिए अंचल के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले सहरिया आदिवासियों को भी संगठित कर उनके अधिकारों तक पहुंच बनाने का काम किया।

आज महात्मा गांधी सेवा आश्रम पूरे देश में शांति, अहिंसा और सद्भावना का एक केंद्र बन गया है जहां से पूरे देश में शांति और अहिंसा का संदेश जा रहा है साथ ही महात्मा गांधी ने देश के सामने जो आर्थिक वैकल्पिक नीति रखी थी उसके दर्शन भी गांधी आश्रम में हो रहे हैं। जहां एक तरफ खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से कढ़ाई और बुनाई के काम से सैकड़ों पुरुष एवं महिलाएं जुड़ी है वहीं दूसरी तरफ मधुमक्खी पालन मैं भी अंचल की महिलाएं आगे आई है। मधुमक्खी पालन से इस अंचल के हजारों बेरोजगार परिवारों को काम मिल रहा है चंबल घाटी क्षेत्र मैं सरसों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है ।

महात्मा गांधी सेवा आश्रम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018 – 2019 खादी एवं ग्रामोद्योग, मधुमक्खी पालन, शोधन पैकिंग तथा विपणन, शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल, खादी एवं ग्रामोद्योग भंडार, खादी प्रशिक्षण, वर्मी कंपोस्ट तथा जैविक खेती, वंचित समुदाय का सशक्तिकरण, जल जंगल जमीन पर लोगों के अधिकार, वंचित समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण, पोषण समृद्ध गांव पर आधारित अभियोजन खाद्य सुरक्षा एवं पोषण कार्यक्रम आदि की उपलब्धियों, प्रभावों एवं क्रियान्वयन आदि विवरण दिया गया है।

संस्था के बारे में.....

संस्था का स्वप्न :

महात्मा गांधी सेवा आश्रम का स्वप्न समानता, सामूहिकता और न्याय पर आधारित अन्याय, अत्याचार और शोषणमुक्त समाज की स्थापना करना है।

संस्था का लक्ष्य :

अपने सपने को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी सेवा आश्रम का लक्ष्य समाज के वंचित वर्ग के लोगों,खासतौर से महिलाओं को जनजागरण और क्षमता विकास के माध्यम से संगठित कर विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाना है, जिससे इन वर्गों के सामाजिक, आर्थिक स्तर को बेहतर किया जा सके।

संस्था के उद्देश्य :

न्याय एवं अहिंसा पर आधारित नये समाज की रचना एवं विविध रचनात्मक प्रयोगों के माध्यम से देश के बहुसंख्यक वंचित समुदाय को सम्मान व स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार को पाने की शक्ति प्रदान कराना संस्था का मुख्य उद्धेश्य रहा है।

महात्मा गांधी सेवा आश्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है–

- वंचित वर्ग को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उनका क्षमता विकास करना।
- महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने व बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी क्षमता का विकास करना।
- ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओ के आर्थिक तथा आजीविका के लिए लघु व कुटीर इकाईयों को बढ़ावा देना।
- जन और तंत्र के बीच समन्वयन स्थापित कर शासकीय योजनाओं के कियान्वयन के लिए सूचना एवं जानकारियों का आदान–प्रदान करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण, वनवासियों तथा आदिवासियों की आजीविका संवर्धन एवं अधिकार की रक्षा के लिए प्रयास करना।
- वंचित वर्ग के परिवारों में बाल अधिकार और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करते हुये शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना ।

संस्था का कार्यक्षेत्र :

महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा देश के 7 राज्यों (उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम और मणिपुर) के 44 जिलों के 62 ब्लाक के 2590 गॉव में, लगभग 1 लाख आदिवासी, दलित और किसान परिवारों के साथ सामाजिक न्याय के लिए कार्य कर रहा है। इसके अलावा समाज परिवर्तन के लिए अहिंसक प्रतिकार के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण एशियाई देशों में साथी संगठनों के साथ मिलकर भी काम कर रहा है।

आश्रम के कार्यक्रम :

महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा के द्वारा मुख्य रुप से चार प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है–

- **जागरूकता एवं क्षमता विकास :** न्याय और अहिंसा पर आधारित समाज की रचना के लिए ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और समाज के हाशिये पर खड़े वंचित समुदाय के परिवारों का सशक्तिकरण और उनके स्वावलम्बन संबंधी कार्य करना।
- **संगठन निर्माण :** प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल और जमीन के संरक्षण और संबर्धन तथा इन संसाधनों पर वंचित वर्ग के अधिकार सुनिश्चित करने के लिये संगठन बनाना और उस संगठन के माध्यम से जन पैरवी करना।
- **लक्ष्य समुदाय का सरकारी सेवाओं तक पहुॅच बनाना :** लक्ष्य परिवारों को विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन योजनाओं का लाभ लेने के लिये क्षमता विकसित करना।
- **लघु एवं कुटीर उद्योग का संचालन :** संस्था के द्वारा विभिन्न प्रकार के लघु और कुटीर उद्योग का संचालन किया जा रहा है।

1. आर्थिक सशक्तिकरण के लिये खादी एवं ग्रामोद्योग आधारित आजीविका का सृजन

● खादी उत्पादन :

खादी वस्त्र नही विचार है – महात्मा गाँधी

खादी का जन्म तो सदियों पूर्व हो गया था, लेकिन वैचारिक रुप से खादी का जन्म महात्मा गांधी द्वारा सन 1915 में अफ्रिका से लौटने के बाद हुआ । खादी वस्त्र नहीं, विचार है, इस सूत्र वाक्य के रचयिता महात्मा गांधी हुये।

खादी और चरखा हमारी आजादी की लड़ाई का कितना प्रमुख हिस्सा रहे हैं यह दोहराने की जरूरत नहीं है. हमारी दो–तीन बुनियादी जरूरतों में एक, वस्त्र की इस लड़ाई को गांधी जी ने टिकाऊ और विकेंद्रित विकास के साथ जोड़ा था।

वर्तमान के दिनों में खादी अंतर–राष्ट्रीय स्तर के प्रसिध्द फैशन डिजाईनर भी एक ब्राण्ड के रूप में अपनाने लगे हैं। वर्तमान में ये इतना लोकप्रिय हो गया है कि विशेष अवसरों पर सभी लोग मुख्य परिधान के रुप में अपनाने लगे हैं । दुनिया भर के डिजाईनरों व्दारा खादी का डिजाईन किया जा रहा है। यह कई रंगो में डिजाईन किया जा रहा है। खादी के सारे रंग त्वचा के लिये अनुकूल है। खादी का उत्पादन पर्यावरण को नुकसाान नहीं पहुँचाता है, यह आसानी से पसीना सोखता है और पहिनने में ठंडा और शुष्क रहता है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रो में खादी की बुनाई और धागे की कताई का काम होता है। पूर्व में यह ग्रामीण, श्रमिकों और किसानों के लिये कपड़े के रुप में होता था लेकिन अब खादी कपडे को उच्च वर्ग के लोग भी पसन्द कर रहे हैं। भारत में अब यह सबसे सुंदर कपडे के रुप में माने जाना लगा है। यह लग्जरी और विशिष्ट्ता का प्रतीक बन गया है !

इसी क्रम में महात्मा गांधी सेवा आश्रम में खादी का उत्पादन और विपणन का कार्य विगत 39 वर्षो से हो रहा है ! पहले दरी–फर्श का काम आश्रम प्रांगण में ज्यादा होता था, विगत कुछ वर्षों में इसका काम कम हुआ है कारण बाजार में मोटी खादी का मांग कम हो जाना है। अब मोटी खादी को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, इसलिये आश्रम में भी मोटी खादी का उत्पादन नहीं करा कर बाजार के मांग के अनुसार साफी, सफेद शर्टिंग, कम्बल का उत्पादन हो रहा है।

नये–नये मांग के अनुसार सूती, उनी, पोली जाकेट, शर्ट, कुर्ता–पाजामा रेडिमेड तैयार कर भण्डारों के द्वारा बेचा जा रहा है। इस वर्ष आश्रम द्वारा उत्पादित साफी और जाकेट की बिक्री बहुत अच्छी हुई। के.वी.आई.सी. द्वारा आबंटित खादी उत्पादन लक्ष्य संस्था ने पूरा किया है।

वर्ष 2018–19 में खादी उत्पादन और बिक्री पिछले वर्षो के तुलना में इस प्रकार हुई :

खादी उत्पादन – उपलब्धियां (लाख रूपयों में)

विवरण \ वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19 (फरवरी तक)
सूती खादी	19.51	20.75	17.75
ऊनी खादी	7.19	7.65	4.65
पॉली वस्त्र	9.68	9.15	9.25
कुल	36.38	37.55	31.65

खादी बिक्री – उपलब्धियां (लाख रूपयों में)

विवरण \ वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19 (फरवरी तक)
सूती खादी	23.85	24.62	25.10
ऊनी खादी	11.07	14.57	17.73
रेशम खादी	3.71	3.68	2.82
पॉली वस्त्र	25.17	25.11	26.57
ग्रामोद्योग	3.24	6.08	6.58
कुल	67.04	74.04	78.80

केन्द्रवार खादी बिक्री (लाख रूपयों में)

विवरण \ केन्द्र	मुरैना	ग्वालियर	श्योपुर	जौरा	व्यापार मेला, ग्वा.	योग
सूती खादी	15.05	7.27	0.96	1.25	0.57	25.10
ऊनी खादी	13.36	0.56	0.76	1.81	1.24	17.73
रेशम खादी	2.42	0.33	0.00	0	0.07	2.82
पॉली वस्त्र	19.39	2.46	1.11	2.57	1.04	26.57
ग्रामोद्योग	3.68	1.28	0.10	1.08	0.44	6.58
कुल	53.90	11.90	2.93	6.71	3.36	78.80

गत वर्ष कि तुलना में इस वर्ष खादी बिक्री में वृध्दि हुई है। बिक्री बढ़ने के वजह से रोजागार में वृद्धि की सम्भावना बढ़ गई है। संस्था के खादी ग्रामोद्योग के काम में लगभग 55% अनुसूचित जाति (दलित वर्ग) के कार्यकर्ता जुड़े हुये हैं।

● खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम :

खादी संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संस्थायें सरकारी सहायता के बिना अपने स्तर पर खादी सम्बंधी कार्यक्रम सुनिश्चित करें, संस्थायें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खादी के कार्य को प्रोत्साहित कर सके, खादी के स्वदेशी सोच को बरकरार रखते हुये कत्तिनों बुनकरों और अन्य कारिगरों को सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलम्बी बनाने के उपाय के रूप में खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम को रखा गया है। आश्रम में खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष 2017–18 में खादी एवं ग्रामोधोग आयोग व्दारा कार्यक्रम शुरु किया गया जिसके अंतर्गत निम्न कार्य हो रहे हैं :

1. **सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना :** एक ही स्थान पर कताई , रंगाई. बुनाई, और सिलाई हो सके इसके लिये सामान्य सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है । इस केंद्र में कोन बाईंडिंग मशीन और बॉबिन बाईंडिन्ग मशीन स्थापित हो चुका है ।

2. **कताई प्रशिक्षण केंद्र :** खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम अंतर्गत आश्रम में चर्खा सूत कताई केंद्र को बनाया गया है, जहां न्यू मॉडल चर्खे से धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है !

3. **कम्प्यूटर केंद्र की स्थापना :** के.आर.डी.पी. के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंधित उत्पादन खरीदी–बिक्री के आँकड़े इकट्ठे किये जाएंगे, जो कि ऑनलाईन होंगे तथा सीधे खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुबंई से कनेक्ट होंगे।

4. **बुनाई केन्द्र :** के.आर.डी.पी. के अंतर्गत लिए गये इनपुट लोन से इस मशीन को गोंबल से मंगाया गया है। इससे खादी के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार होगा।

सामान्य सुविधा केंद्र

कताई प्रशिक्षण केंद्र

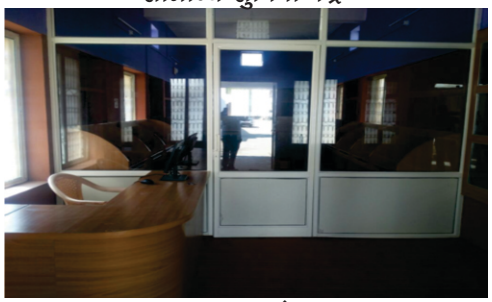
कम्प्यूटर केंद्र

बुनाई केन्द

• शहद एवं मधु मक्खी पालन :

मधु,परागण आदि की प्राप्ति के लिये मधुमक्खियां पाली जातीं हैं। यह एक कृषि आधारित उद्योग है। मधुमक्खियां फूलों के रस को शहद में बदल देतीं हैं और उन्हें अपने छत्तों में जमा करतीं हैं। जंगलों से मधु एकत्र करने की परंपरा लंबे समय से लुप्त हो रही है। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में स्थापित हो चला है। मधुमक्खी पालन के उत्पाद के रूप में शहद और मोम आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा के द्वारा विगत सन 1999 से मधुमक्खी पालन एवं जंगली शहद निष्काशन का प्रशिक्षण दे रहा है। शहद निष्काशन का प्रशिक्षण ''केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण संस्थान (खादी एवम ग्रामोधोग आयोग) पुणे'' के सहयोग से दिया गया है, प्रशिक्षण वैज्ञानिक विधि से शहद निष्काशन का दिया जाता है जिससे मधुवंश और शहद के गुणवता पर प्रभाव न पड़े।

आश्रम द्वारा 345 शहद संग्रहण करनेवाले (honey hunters) और 610 मधुमक्खी पालक को प्रशिक्षित किया गया है। संस्था मुख्य भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन, उत्पादित माल की बिक्री में सहायता प्रदान करना है। मधुमक्खी पालन उधोग एक ग्रामोधोग कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन का सशक्त माध्यम तथा ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मधुमक्खी पालन स्वरोजगार का एक अच्छा साधन सिध्द हो रहा है तथा वर्तमान में अरबों डॉलर का अंतराष्ट्रीय बाजार में इसका विपणन होता है। यह व्यवसाय मध्यप्रदेश में काफी लोकप्रिय हो रहा है। मध्यप्रदेश के चम्बल क्षेत्र के मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, ग्वालियर जिले में यह व्यवसाय काफी अच्छा उभर कर आ रहा है। देश के अधिकांश भू–भाग फसलों, सब्जियों, फलोधानों, जडी–बूटियों, वनों, फूलों, एवं औषधीय पौधों से आच्छादित हैं। जो प्रतिवर्ष फल व बीज के साथ ही साथ पुष्परस और पराग को धारण करते हैं किंतु उसका भरपुर सदुपयोग नहीं हो पाता है बल्कि इस बहूमुल्य उपज के अंश का दोहन न किये जाने से धूप, वर्षा एवं ओलों के कारणवश प्रकृति में पुनः विलीन हो जाता है। प्रकृति के इस अनमोल उपहार को मधुमक्खीयों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, उसे ही ''मधु'' कहते हैं।

शहद संग्रहण प्रशोधन एवं विपणन :

वर्ष 2018–19 में संस्था ने क्षेत्र के सभी मधु मक्खीपालकों से बिभिन्न प्रकार के शहद का संग्रहण किया गया। जिसका प्रशोधन और बॉट्लिंग कर शहद का विपणन किया गया। इस वर्ष रोजगार संख्या में भी व्यावसायिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुरैना जिला एन. एच.–3 आगरा मुम्बई रोड व मेंन रेलवे लाईन से जूड़ा हुआ है, इसलिये यहां बाहर के व्यापारी भी शहद खरीदने के लिये आकर्षित होते हैं।

संग्रहण/खरीद	बिक्री	रोजगार संख्या
987654.00	1298765.00	280

मुरैना जिले में शहद उत्पादन व विपणन की बहुत सम्भावानायें हैं। मुरैना जिले के 70 प्रतिशत लोग कृषि आजीविका पर आधारित है। कृषि के अतिरिक्त, मधुमक्खी पालन व्यवसाय एक साथ किया जा रहा है !

हनी मिशन से किसानों को जोड़ना :

भारत सरकार व्दारा चलाये जा रहे हनी मिशन के अंतर्गत मुरैना और श्योपुर जिले के 125 किसानो को आश्रम व्दारा खादी एवं ग्रामोधोग के माध्यम से जोड़ा गया है । सभी किसानों को 25–25 के समुह में प्रशिक्षित कर 10–10 मधुमक्खी बॉक्स अन्य जरुरी समान दिया गया है ,जिससे किसानों के आय में वृध्दि हो सके। शुरुआती वर्ष मे ही 1250 मधुमक्खी बॉक्स किसानों को दिया गया है। इस वर्ष किसानों द्वारा 8972 किलो शहद का उत्पादन किया गया है।

• केंचुआ खाद या वर्मीकम्पोस्ट

केंचुआ खाद या वर्मीकम्पोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है।वर्मी कम्पोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते है तथा वातावरण प्रदूषित नहीं केंचुआ खाद की विशेषताएँ रू इस खाद में बदबू नहीं होती है, तथा मक्खी, मच्छर भी नहीं बढ़ते है जिससे वातावरण स्वस्थ रहता है। इससे सूक्ष्म पोषित तत्वों के साथ–साथ नाइट्रोजन

2 से 3 प्रतिशत, फास्फोरस 1 से 2 प्रतिशत, पोटाश 1 से 2 प्रतिशत मिलता है।

- इस खाद को तैयार करने में प्रक्रिया स्थापित हो जाने के बाद एक से डेढ़ माह का समय लगता है।
- प्रत्येक माह एक टन खाद प्राप्त करने हेतु 100 वर्गफुट आकार की नर्सरी बेड पर्याप्त होती है।
- केचुँआ खाद की केवल 2 टन मात्रा प्रति हैक्टेयर आवश्यक है।
- केचुँए से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है।
- भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ती है।
- भूमि का उपयुक्त तापक्रम बनाये रखने में सहायक।
- भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा। अतः सिंचाई जल की बचत होगी। केचुँए नीचे की मिट्टी ऊपर लाकर उसे उत्तम प्रकार की बनाते हैं।
- केचुँआ खाद में ह्यूमस भरपूर मात्रा में होने से नाइट्रोजन, फास्फोरस पोटाश एवं अन्य सूक्ष्म द्रव्य पौधों को भरपूर मात्रा में व जल्दी उपलब्ध होते हैं।
- भूमि में उपयोगी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है।

आश्रम में केंचुआ खाद का उत्पादन व प्रचार– प्रसार निरंतर किया जा रहा रहा है। इस वर्ष 57000.00 की खाद बिक्री हुई।

2. "कुपोषण से मुक्ति अभियान" में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधिता कार्यक्रम

श्योपुर जिले के 3 ब्लॉक के 226 पंचायतों के 527 गांवों में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधता कार्यक्रम संचालित है। यह कार्यक्रम जर्मनी के जी.आई.जेड., वेल्थ हंगर हिल्फे तथा महात्मा गांधी सेवा आश्रम के संयुक्त प्रयास से चलाया जा रहा है। उक्त दोंनो संस्थाओं ने श्योपुर जिले में अति कम वजन के बच्चे और एनिमिया से पीड़ित महिलाओं में पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के तहत वंचित समुदाय की महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर चुना गया क्योंकि महिला ही है जो परिवार को सही पोषण प्रदान कर पाती है। श्योपुर जिले की इस समस्या से निपटने के लिये आवष्यक था कि इस कार्यक्रम में शासन को भी शमिल किया जाये। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग ओर हॉर्टिकल्चर विभाग के मुख्य सचिवों से बातचीत की गई और यह तय हुआ कि महिला बाल विकास के अन्तर्गत कार्यरत् आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण से जोड़ कर योजनाओं को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाये। इस परियोजना के उद्देष्य प्राप्ति के लिए 32 लोगों की परियोजना–टीम बनाई गई जो सघन रुप से 50 गांवों में काम करने लिये जिम्मेदार हैं।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य :

- ✓ 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के स्वास्थ्य ओर पोषण स्तर में वृद्धि करना।
- ✓ 0 से 23 माह के बच्चों के न्यूनतम पोषण मानक में वृद्धि।

परियोजना के कार्यक्षेत्र :

इस परियोजना के तहत श्योपुर जिले के कुल 50 गांवों (कराहल ब्लाक के 35 तथा श्योपुर ब्लाक के 15) में सघन रुप से काम किया जा रहा है जबकि सम्पूर्ण श्योपुर जिले के 527 गांवों में 1138 आंगनबाडियों केंद्रों के माध्यम से काम किया जा रहा है।

मुख्य गतिविधियाँ :

1. मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण
2. आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण
3. पी.एल.ए बैठकों का आयोजन
4. सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन पद्धति
5. स्टाफ ट्रैनिंग प्रोग्राम मास्टर टीओटी
6. आईसीडीएस पर्यवेक्षक प्रशिक्षण

मुख्य उपलब्धियाँ :

1. सहभागी सीख प्रक्रिया के अंतगर्त वर्ष 2018–19 में 1138 आगनबाड़ियों को प्रशिक्षत किया गया।
2. समुदाय के साथ मिलकर पोषण से संबंधित स्थानीय समस्याओं को पहचाना गया, उनका प्राथमिकीकरण किया गया, उनके अर्न्तनिहित कारणों को समझने का प्रयास किया गया और उनपर काम करने की रणनीति बना कर उसे क्रियान्वित किया गया।
3. समुदाय के अन्तर्गत पोषण में विविधता के महत्व पर समझ विकसित किया गया और पोषणबाड़ी तैयार करके खाद्यसुरक्षा सुनिष्चित करने का प्रयास किया गया।
4. बच्चों में उपरी आहार की सही समय पर शुरूआत व स्तनपान के महत्व, स्थानीय खाद्य सामग्रियों से तैयार किये जा सकने वाले पौष्टिक भोजन की विधि आदि पर जागरुकता स्तर बढ़ाया गया।
5. 6 सें 24 महीने के बच्चों के लिए माताओं ने पौष्टिक भोजन तैयार करखिलाया और माना कि ये आसान है और हम इससे अपने बच्चों का पोषण स्तर बढ़ा सकते है।
6. आज हर मां बच्चों को हाथ धो कर खाना खिला रही है। साथ ही बच्चों को भी सही तरीके से हाथ धोना सिखा रही है।
7. पोषणबाड़ी – खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधता कार्यक्रम के अंतर्गत दुसरी रणनीति घर–घर में पोषणबाड़ी बनाने का था जिसके अंतर्गत 2018–19 में 4000 परिवारों का लक्ष्य पुरा किया गया। इन पोषणबाड़ियों के लिये वन विभाग ने 15550 फलदार वृक्ष दिये ओर 550 किट हॉर्टिकल्चर विभाग ने समुदाय को प्रदान किये।

26 जनवरी 2019 श्योपुर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा पोषण रथ के माध्यम से पोषण समृद्ध ग्रम अभियान की झाकी का प्रदर्शन

परियोजना के कार्यकाल में आयोजित गतिविधियाँ

क्रं.	गतिविधि	आयोजन संख्या	पुरूष	महिला	किशोरी
1.	गोदभराई	172	128	2348	680
2.	अन्न प्राशन	178	136	1324	598
3.	जन्म दिवस	196	142	1971	1003
4.	किशोरी दिवस	195	103	7273	591
5.	फूड डेमोस्ट्रेशन	1291	744	3109	1332
6.	हाथ धुलाई	1034	839	3551	1904
7.	आहारीय विविधता	2604	1827	5903	2142
8.	ग्रह भेंट	18764	10287	25676	12530
9.	वजन अभियान	219	2205	4162	960
10.	लालिमा अभियान	74	710	1729	1454
11.	बाल चौपाल	419	1078	1766	3385
12.	टीकाकरण	113	201	1353	1596
13.	एन. आर. सी. विजिट	17	39	124	06
14.	जन संवाद	33	574	669	90
15.	रोजगार बैठक	34	350	514	157
16.	जल संवाद	919	954	277	
17.	शौचालय हेतु जागरूकता	662	784	1672	816
18.	दस्तक अभियान	8	53	67	82
19.	बीजबैक	35	70	235	80
20.	स्नेह शिविर	13	30	16	10
21.	सुपोषण अभियान	3	57	47	31
22.	ग्राम सभायें	21	416	366	54

जन पैरवी के तहत किये गये कार्य

क्रं.	जन पैरवी के मुद्दे	उपलब्धियाँ	रिमार्क
1.	पी डी एस की सेवाओं में सुधार	17	
2.	एम डी एम	17	
3.	तालाब गहरीकरण	187	नवीन तालाब 90 एवं मरम्मत 77
4.	आई सीडी एस के फोकस ग्राम में कार्य	50	88 आंगनबाडी
5.	हेण्डपम्प मरम्मत	657	673 आवेदन
6.	वृद्धावस्था पेन्शन	457	
7.	विधवा पेन्शन	227	
8.	पोषण बाडी	4000	
9.	राशन कार्ड	1412	1605 आवेदन
10.	आवास	766	1260 आवेदन
11.	पात्रता पर्ची	1279	1384
12.	भूमि हेतु आवेदन	43	43
13.	शौचालय	1458	1533
14.	गैस कनेक्शन हेतुआवेदन	507	1058

कुपोषण में सहभागी सीख प्रकिया से निकले बदलाव :

- आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषण आहार समय पर मिलने लगा है।
- नियमित वजन व टीकाकरण होने लगा है ।
- एन.आर.सी में को कमजोर बच्चों को लेकर माता पिता का स्वयं से आने लगे है। आंगनबाड़ी स्वयं फोलोअप भी करती है व माता पिता को जानकारी रहती है।
- एन.आर.सी में परिजनों के साथ मैत्री पूणे व्यवहार जो पहले नहीं होता था अब होने लगा है ।
- आंगनबाडी केन्द्रों पर भोजन राशि समय पर पहुंचने से बच्चों को डाईट मिलने लगी है।
- समुदाय में व्यवहार परिवर्तन को देखा जा सकता है। अब परिवार का साफ सफाई पर अधिक ध्यान देना ।
- स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर गांव में शौचालय निर्माण कराना तथा उसका उपयोग करना।
- प्रत्येक परिवार में पोषण बाडियां लगा कर उसमें होने बाली सब्जियों का प्रयोग किया जाने लगा।
- पोषण संबंधी आदतों मे परिवर्तन हुआ।
- माँ में ऊपरी आहार पर समझ बनी है ओर बच्चों में वजन भी बढ़ा।
- बच्चों को उम्र के अनुसार भोजन दिया जाने लगा।
- समुदाय में भेदभाव व रूढीवादिता कम हुई ।

केस स्टडी : शिवानी और रमा

श्योपुर से 8 किमी दूर एक गांव है – नगदी। गांव मुख्यतः दो भागों में बंटा है – एक तरफ जहां समृद्ध लोग रहते हैं वहीं दूसरी ओर वंचित समुदाय के लोग निवास करते हैं। सर्वे के अनुसार गांव की जनसंख्या लगभग 1218 है।

इस गांव के आदिवासी बस्ती में निवासरत एक परिवार है रामचन्द्र आदिवासी का। रामचन्द्र आदिवासी अपनी पत्नी विलासी व अपनी दो बेटियों शिवानी व रमा के साथ रहते हैं। रामचन्द्र का परिवार गांव में भुखमरी की स्थिति में जीवनयापन कर रहे थे। लगभग 2 साल से रामचन्द्र स्वंय बीमार हैं, उसकी स्थिति नाजुक होने के कारण वह अपना इलाज नही करा पा रहे हैं। इस स्थिति में घर के भरण–पोषण की जिम्मेदारी उसकी पत्नी की है। विलासी पास के ही समृद्ध ब्राह्मण परिवार में गोबर साफ करने का कार्य करती हैं जिससे उसे प्रति माह 50 किलो गेहूँ मिल जाते हैं। कुछ खाद्यान्न वह पी.डी.एस. से प्राप्त कर लेती है। गरीबी के कारण विलासी अपनी दोनो बेटियों को पौष्टिक भोजन तक नही दे पा रही हैं जिसके कारण दोनों बेटियां शिवानी (ढाई वर्ष) और रमा (6 माह) कुपोषण की शिकार हैं। ऐसी स्थिति में दोनों मासूम बच्चियां शिवानी और रमा लगातार कमजोर होती गई और बहुत बीमार पड़ गई। इस गांव में महात्मा गाँधी सेवा आश्रम द्वारा खाद्य सुरक्षा एंव पोषण विविधता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जब गाँव में सहभागी सीख प्रक्रिया की बैठकें संचालित हुई तो विलासी को भी पी.एल.ए. बैठकों से जोड़ने का प्रयास किया गया। विलासी से उसकी बेटियों के बारे में चर्चा की गई तो उसका उत्तर था कि क्या करें। संस्थागत प्रयास के बाद शिवानी को एन.आर.सी. में भर्ती कराया गया। पूरे 14 दिन बाद जब विलासी अपनी बेटी शिवानी के साथ वापस आई तो उसकी बेटी में वजन वृद्धि न के बराबर ही हुई थी, लेकिन विलासी लगातार पी.एल.ए. बैठकों में आती रही। उसे अपने घर में एक अच्छी पोषणबाड़ी लगाने की सलाह दी गई और उसे संस्था की ओर से पौधे व बीज प्रदान किये गये। विलासी ने भी ठीक वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया। उसने एक बड़ी सी जगह में जो उसके घर के पास खाली पड़ी थी बाड़ी लगाई। संस्था की कार्यकर्ता ने विलासी को सलाह दी कि अपनी बेटियों के भोजन में कुछ बदल–बदल कर भोजन दो, साथ ही व्यक्तिगत साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दो। साबुन से हाथ धोने के तरीके व स्तनपान निरंतर कितनी बार और कैसे कराना है, यह भी बताया गया। विलासी ने ठान लिया कि वह स्वयं की देखभाल से अपनी बेटियों को स्वस्थ्य करेगी, साफ–सफाई पर ध्यान देगी और सब्जियों को अपने बच्चों के खानपान में सम्मिलित करेगी। परिणामस्वरूप विलासी व उसकी बेटियों के जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव हुआ। 3 महिने में उसकी दोनों बेटियों की स्थिति में परिणाम दिखे। उसकी बड़ी बेटी पूर्णरूप से स्वस्थ्य हो गई व उसकी छोटी बेटी रमा में भी बहुत सुधार हुआ।

कहते हैं कि अगर व्यक्ति ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है विलासी ने कुछ ऐसा ही किया। अब विलासी बहुत खुश है और इस वर्ष भी उसने घर में सहजन के पौधे लगाए हैं और सब्जियों के बीज भी तैयार किये हैं।

3. बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ कार्यक्रम श्योपुर

महात्मा गांधी सेवा आश्रम देश के ऐसे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों की लडकियों को शैक्षिक अवसर प्रदान करता है जिनकी पारंपरिक रूप से स्कूली शिक्षा तक कोई पंहुच नहीं है। कार्यक्रम का उद्देश्य निरक्षरता के चक्र को तोड़ना है। यह समुदाय–आधारित शिक्षण केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। जहां वे 5 वर्ष तक निरंतर और सहज शिक्षा प्राप्त करते है और मुख्यधारा की शिक्षा में प्रवेश के लिये निर्देशित होते है।

कार्यक्रम की दृष्टि बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण द्वारा भारत में महिलाओं, परिवारों और पूरे समुदायों के जीवन को बदलना है। और हमारा मिशन भारत के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछडे ग्रामीण क्षेत्रों में 06 से 14 साल की विधालय न जाने वाली एंव शालात्यागी या अप्रवेसी वालिकाओं को प्रेरित कर उन्हे गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से साक्षरता की राह पर मजबूती से खड़ा करना है।

कार्यक्रम की संरचना :

क्रं.	कार्यक्रम का नाम	कुल केन्द्र	कुल शिक्षक	कुल छात्राएँ	कुल गाँव	कुल पंचायत
1.	बेटी पढाओं केन्द्र, ब्लॉक–कराहल जिला–श्योपुर (म.प्र.)	40	40	1030	31	19
2.	बालिका शिक्षा कार्यक्रम बडौदा जिला–श्योपुर (म.प्र.)	44	44	1072	41	31
	कुल	84	84	2102	72	50

कार्यक्रम का उद्देश्य :

1. विद्यालय न जाने वाली सभी बालिकाओं के लिये सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से बुनियादी प्राथमिक शिक्षा

में नामांकन बढाना और उन्है प्रोत्साहित करना।

2. बेटी पढाओं केन्द्रों के माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
3. प्रत्येक बालिका को एक स्वतंत्र विचारक और आत्म शिक्षार्थी बनने के लिये प्रोत्साहित और सक्षम करना।
4. शिक्षा को रूचीपूर्ण बनाना।
5. शिक्षा के माध्यम से समुदाय के जीवन स्तर को बदलना।

कार्यक्रम का परिचय एंव पृष्ठभूमि :

बालिका शिक्षा कार्यक्रम अगस्त 2017 से कराहल एंव बडौदा ब्लॉक के सुदूर क्षेत्रों में सहरिया आदिवासी बालिकाओं के लिये 84 बेटी पढाओं केन्द्रो का संचालन महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा किया जा रहा है। इन 84 केन्द्रो में 2102 आदिवासी बालिकाओं को शिक्षित करने का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम उन समुदाय की बालिकाओ के लिये किया जा रहा है जो या तो बालिका शिक्षा को जरूरी नहीं समझते या जिनके लिये शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। इन परिवारों में शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। इन परिवारों की बालिकाओं का शासकीय विधालय में नाम दर्ज तो है परन्तु इन परिवारों की बालिकाओं की विधालय में उपस्थिति बहुत ही कम होती है क्योंकि इन परिवारों की अधिकतर बालिकाऐं घरेलू कामों जैसे– भेड–बकरी चराना, छोटे भाई–बहनों की देखभाल करना, माता–पिता के साथ मजदूरी पर जाना, जंगलो से औषधियॉ इकठ्ठा करना, पानी भरना, खेतो की देखभाल करना आदि में व्यस्त रहती है। बालिकाओं की शादी कम उम्र में कर दी जाती है जिससे इनके स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पढता ही है और उनकी पढाई भी बीच में ही छूट जाती है।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुऐ महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा बालिका शिक्षा की स्थिति में सुधार करने हेतु यह कार्यक्रम चलाया गया। इन केन्द्रों को खोलने से पूर्व समुदाय के लोगों के साथ बैठकें कर इस कार्यक्रम के उद्देश्य एंव महत्व के बारे में उन्हें बताया गया एंव अपनी बालिकाओं को केन्द्र में नामांकन कराकर रोजाना केन्द्र में भेजने पर चर्चा की गई एंव सभी की सहमति से केन्द्र खोला गया।

इन केन्द्रों से बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला एंव बालिकाऐं स्वंय की रूची से केन्द्रों में आने लगी हैं। बालिकाऐं साफ–सफाई के महत्व को भी जानने लगी है और उनके रहन–सहन, बोल–चाल में भी परिवर्तन हुआ है।

1. जिन समुदायों में बालिकाओं को प्राथमिक कक्षा तक भी नहीं पढाया जाता था उन समुदाय से लगभग 250 बालिकाओं ने शासकीय विधालयों एंव कन्या छात्रावासों में प्रवेश लिया है एंव वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रही है।
2. इस बालिका शिक्षा कार्यक्रम में 84 स्थानीय शिक्षको द्वारा शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा बालिकाओं को खेल–खेल में गतिविधि द्वारा एंव शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री का बेहतर तरीके से उपयोग कर शिक्षा देने का कार्य किया जाता है जिससे बालिकाओं को शिक्षा बोझ न लगते हुऐ वे इसे रूची के साथ शिक्षण कार्य में अपनी सहभागिता देती है।
3. इस कार्यक्रम के द्वारा स्थानीय स्तर पर लगभग एक सैकडा लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है।
4. शिक्षकों की क्षमतावृध्दि के लिये इस कार्यक्रम के तहत् संस्था द्वारा प्रत्येक तीन माह में 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है जिसमें शैक्षिक कौशल, गतिविधि आयोजन, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग

करना सिखाया जाता है। इन प्रशिक्षणो के माध्यम से शिक्षको को स्वंय के व्यक्तिगत कौशल को बढाने का भी अवसर प्राप्त होता है।

5. कार्यक्रम के द्वारा सामुदायिक बैठके कर समुदाय के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर उनकी शिक्षा के कार्यो में भागीदारी बढाने का कार्य भी संस्था द्वारा किया जा रहा है।

6. सामुदायिक बैठकों का परिणाम यह हुआ है कि बालिकाओं के माता–पिता एंव समुदाय के लोग शिक्षा के प्रति अपनी रूची लेने लगे है एंव बेटी पढाओं केन्द्रो की हर संभंव मदद भी करते है। वे अपनी बालिकाओं को नियमित केन्द्र पर भी भेजने लगें है कहीं–कहीं जहॉ बेटी पढाओं केन्द्रो के संचालन के लिये कोई स्थान नहीं था वहॉ समुदाय ने अपने खाली पडे कमरों को केन्द्र संचालन के लिये प्रदान किया है।

7. महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा इन 84 केन्द्रों में समय–समय पर सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

इस प्रकार से स्थानीय स्तर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से बालिका शिक्षा में सुधार हेतु अनेक सफल प्रयास किये गये हैं। सहरिया आदिवासी समुदाय के बीच में शिक्षा की अलख जगाने में इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

केस स्टडी :

विद्यार्थी का नाम : फोरन्ती आदिवासी **पिता : स्व. नेकराम आदिवासी**
माता : श्रीमती कस्तुरी आदिवासी **जन्मतिथि : 19 फरवरी 2007**
वर्तमान स्तर : 9 **केन्द्र का नाम : बांराभेरू**

बारांभेरू गॉव में एक लड़की फोरन्ती अपने गरीब परिवार के साथ रहती है। एक लम्बी बिमारी के कारण उसके पिता की मृत्यू कुछ वर्ष पूर्व हो गई थीं। पिता की मृत्यू के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारियों का भार फोरन्ती की मां एवं उसके कंधे पर आ गया था। तब फोरन्ती और उसकी मॉ ने घर में एक मुर्गी पालन फार्म खोला। फोरन्ती अपनी मां के साथ जंगल से लकडियॉ इकट्ठा करके उसे गॉव में बेचने भी जाती थीं। उनके पास रहने के लिये स्वयं का घर भी नहीं था। फोरन्ती पढ़ता चाहती थी परन्तु घर की समस्याओं के कारण उसकी मां उसकी षिक्षा पर ध्यान नहीं देती थीं। जब भी शिक्षक फोरन्ती को घर पर बुलाने जाता, तब उसकी मां षिक्षक को एक ही जबाब देती थीं कि अगर हम फोरन्ती को पढ़ने भेज देगें तो घर पर काम कौन करेगा और अपने छोट भाई–बहनों की देखभाल कौन करेगा। जब भी फोरन्ती की मां कहीं काम पर जाती तो फोरन्ती अपनी मां को बिना बताये बेटी पढ़ाओ केन्द्र पर पढ़ने के लिये आ जाती थीं। फोरन्ती की षिक्षा के प्रति इस लगन को देखते हुये शिक्षक ने फोरन्ती की मां को निरन्तर समझाने का प्रयास जारी रखा। षिक्षक ने फोरन्ती की मां को कई बार समझाया कि फोरन्ती पढ़ने में बहुत होषियार है और उसमें पढ–लिख कर कुछ बनने की क्षमताऐं भी है। शिक्षक ने बालिका शिक्षा से होने वाले लाभ, उसकी आवष्यकता और वर्तमान में रोजगार में महिलाओं के लिये जो अवसर शासन द्वारा दिये जा रहे है उनके बारे में भी बताया। आखिरकार शिक्षक की मेहनत रंग लाई और धीरे–धीरे फोरन्ती की मां को षिक्षा का महत्व समझ में आने लगा और अब वो फोरन्ती को केन्द्र के समय में कोई काम नहीं देती है और फोरन्ती को नियमित बेटी पढ़ाओं केन्द्र भेजती है। अब फोरन्ती बहुत खुश है। फोरन्ती की मां का कहना है कि अब में षिक्षा के महत्व को जान गई हूॅ और फोरन्ती भी आगे पढ़ना चाहती है इसलिये मैं उसे आगे पढाऊॅगी। फोरन्ती इस कार्यक्रम संचालन के लिये महात्मा गांधी सेवा आश्रम को धन्यवाद देती है।

4.चाइल्डलाइन के माध्यम से आपातकालीन पहुंच सेवा - श्योपुर

बच्चों की देखरेख और संरक्षण की जरूरत के लिए चाइल्डलाइन प्रतिदिन 24 घंटे आपातकालीन राष्ट्रीय फोन पहुंच सेवा है जो बच्चों को आपतकालीन और दीर्घ अवधि देखरेख तथा पुनर्वास सेवाओं से जोड़ती है। कठिन परिस्थिति में रहने वाला कोई भी बच्चा या उसकी ओर से कोई वयस्क इस सेवा तक 1098 डायल करके पहुंच सकता है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में इस सेवा को स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह सेवा देश के 281 शहरों तथा मध्य प्रदेश के 2 शहरों में प्रचालनरत है। देश के सभी भागों में बच्चों को एक संरक्षात्मक परिवेश प्रदान करने के लिए आई.सी.डी.एस. में सभी जिलों /शहरों तक चाइल्डलाइन सेवा के विस्तार की कल्पना की गई है। शहर के स्तर पर चाइल्डलाइन कार्यक्रम मे शहर स्तरीय सलाहकार बोर्ड, एक नोडल संगठन और एक सहयोगी संगठन शामिल होगा। चाइल्डलाइन की स्थापना जून 1996 मे हुई थी, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार, दूरभाष विभागों, स्थानीय युवा समूहों, अशासकीय संगठनों, निगमों तथा संबद्ध व्यक्तियों की सामूहिक व सक्रीय भागीदारी के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु नेटवर्क तैयार किया जाता है। चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन इसके लिये नोडल संस्था है जिसके माध्यम से देश के समस्त चाईल्डलाइन का संचालन किया जाता है।

परियोजना का उद्देश्य :

चाइल्डलाइन 0–18 वर्ष के बालक/बालिकाओं के देखरेख व संरक्षण हेतु कार्यरत निःशुल्क आपतकालीन दूरभाष तथा आउटरीच सेवा है जिसके अंतर्गत आवश्यकतानुसार दीर्घकालीन सेवा भी प्रदान की जाती है। चाइल्डलाइन 1098 पर कोई भी बालक अथवा संबंधित व्यस्क 24 घंटे (दिन या रात) कभी भी संपर्क कर सकता है। बालक बालिकाओं के लिए सुरक्षित नेटवर्क का निर्माण कर सहज पहुँच बनाना चाइल्डलाइन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त भी निम्नलिखित कई उद्देश्य हैं–

- प्रत्येक 0 से 18 वर्ष के जरूरतमंद बच्चों की मदद करना।
- यदि कोई बच्चा बीमार हो, अकेला हो तो उसकी सहायता करना।
- किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत हो तो उसकी सहायता करना।
- कोई बच्चा छोड़ दिया गया हो या गुम हो गया हो तो उसकी सहायता करना।
- किसी बच्चे का शोषण हो रहा हो या रास्ते पर किसी बच्चे का उत्पीड़न हो रहा हो तो उसकी सहायता करना।
- 14 वर्ष से आधिक उम्र के बच्चों से काम करवा कर बच्चे को मजदूरी नहीं दी गई हो तो उसकी सहायता करना।

सहयोगी संगठन की भूमिका तथा कार्य :

- राष्ट्रीय टोल फ्री नम्बर 1098 पर आने वाली कॉल का उत्तर देना और देखभाल और सरंक्षण की दृष्टि से जरूरतमंद बच्चों के लिए बचाव और आपातकालीन सेवा का प्रावधान करना।
- 60 मिनट के अंदर बच्चे की मदद के लिये पहुंच बनाना।
- संबद्ध स्थानीय विभाग जैसे पुलिस, प्रशासन, श्रम, स्वास्थ्य रेलवे आदि की सहायता से बचाव तथा अन्य आउटरीच सेवाओं का समन्वय करना।
- देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को बाल कल्याण समिति (सी.डब्लू.सी.) के समक्ष पेश करना।
- चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 के बारे मे जागरूकता फैलाना।
- उन उच्च जोखिम क्षेत्रों का पता लगाने के लिए शहर का मानचित्रण करना जहां असुरक्षित बच्चे मिलते हैं।
- दैनिक आधार पर हस्तक्षेप तथा मामला अनुवर्तन।
- दैनिक आधार पर समुदाय में आउटरीच तथा जागरूकता।
- नोडल संगठन को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- केस का नियमित फॉलोअप करना।

परियोजना प्रगति एवं परिणाम :

- अप्रेल 2018 से फरवरी 2019 तक कुल 401 केस दर्ज हुए हैं जिसमें मेडीकल के 190, स्पोंसरशिप के 137, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूस के 14, (चाइल्ड मेरिज के 02, चाइल्ड बेगरी के 5, फिजीकल व मेन्टल व अब्यूस के 5, चाइल्डलेबर के 1) शेल्टर के 19, मिसिंग के 31, डिड नोट फाइन्ड/ नोट इन्टरवेषन के 09 केस रजिस्टर हुये हैं।
- वर्ष 2018–19 मे चाइल्डलाइन टीम द्वारा की गयी कुल आउटरीच की संख्या 1100 है जिसमे इन्डीविजुअल आउटरीच 910, स्मॉल ग्रुप आउटरीच 70, ग्रुप आउटरीच 30 तथा नाइट आउटरीच 35 हैं।
- लापता स्थिति में मिले 23 बच्चों के परिवार के बारे में पता कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनको सुरक्षित उनके परिवार तक पहुँचाया गया।
- 3 बालक बालिका जो घर से लापता हुए या भाग गये थे उनके बारे मे पता कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनको सुरक्षित उनके परिवार तक पहुँचाया गया।

- 4 बच्चों व उनके माता पिता की काउन्सलिंग करके बच्चों का भीख मांगना बन्द करवाया गया।
- 4 बच्चों जिनके साथ शारीरिक या मानसिक शोषण किया गया था चाइल्डलाइन टीम द्वारा इस विषय की जानकारी पुलिस, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण समिति व सम्बंधित विभाग को दे कर बच्चों की मदद करवायी गयी।
- 3 अनाश्रित रूप से मिले बच्चों के अस्थाई रूप से रहने की व्यवस्था बाल कल्याण समिति की मदद से करवाई गयी।
- 16 अनाथ बच्चे जिनके माता–पिता की मृत्यु हो गयी है या रिश्तेदार/ दादा–दादी की आर्थिक व शारीरिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चों का पालन–पोषण करने में परेशानी आ रही है, चाइल्डलाइन टीम द्वारा इन सभी बच्चों की जानकारी महिला सशक्तिकरण विभाग एवं बाल कल्याण समिति को दे दी गयी है व समय–समय पर इन केसो का फोलोअप किया जा रहा है जिससे इन बच्चों को भी लाभ दिलवाया जा सके।
- 16 बच्चें जिनको थेलिसीमिया, हिमोग्लोबिन की कमी अथवा अन्य बीमारी होने के कारण इन बच्चों को रक्त की तुरन्त आवश्यकता थी। इस दौरान ब्लड बैंक मे रक्त नही होने की स्थिति मे चाइल्डलाइन टीम सदस्यों द्वारा रक्तदान करने वाले लोगो व स्वयं टीम सदस्य द्वारा भी रक्तदान किया गया जिससे बच्चों के स्वस्थ्य मे सुधार हुआ।
- 92 बच्चों जिनको बुखार, शारीरिक चोट, एक्सीडेंट, कुत्ते का काटना आदि स्वास्थ्य से सम्बंधित समस्याएं होने पर टीम सदस्य द्वारा बच्चों को जिला अस्पताल में उपचार करवाया गया।
- 13 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे जिनके माता–पिता बच्चो को एन.आर.सी. मे भर्ती नही करवा रहे थे उन बच्चों के माता –पिता की काउन्सलिंग करके बच्चों को जिला अस्पताल के एन.आर.सी. मे भर्ती करवाया गया व भर्ती के दौरान समय–समय पर पहुंचकर कर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकरी ली गयी जिससे बच्चों के स्वस्थ्य मे सुधार हुआ।
- 61 बच्चों व उनके माता–पिता की काउन्सलिंग करके बच्चों का टीकाकरण करवाया गया।
- 23 बालक व बालिकाओं जिनके माता–पिता बच्चों को स्कूल में भर्ती नही करा रहे थे, चाइल्डलाइन टीम द्वारा माता–पिता की काउन्सलिंग करके बच्चों को स्कूल मे भर्ती करवाया गया।
- 7 बालक व बालिकाओं जिनको स्कूल से सम्बंधित समस्याएं जैसे फीस के लिये परेशान करना, छात्रवृत्ति न मिलना, एडमिट कार्ड न देना आदि होने पर चाइल्डलाइन टीम द्वारा स्कूल के विभाग प्राचार्य से बातचीत कर बच्चों की मदद की गयी।
- 26 बालिकाओं के माता–पिता को योजना के बारे मे जानकारी दे कर व उनकी काउन्सलिंग कर बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़वाया गया।
- 3 शारीरिक एवं मानसिक विकलांग बालक व बालिकाओं के विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाये गये जिससे उन्हें विकलांगो से सम्बन्धित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होने लगा।
- पी.एच.ई. विभाग की मदद से 2 स्कूल के हेण्डपंप को सही करवाकर छात्र–छात्राओं को पीने का पानी उपलब्ध करवाया गया।

5. कस्तुरबा गांधी छात्रावास की बालिकाओं में जल स्वछता एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार परिवर्तन। ''प्रज्वला''

मानव विकास में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है शिक्षा के अभाव में हम कहीं न कहीं पिछड़े हैं एवं अनेक प्रकार के लाभ से वंचित हैं। सरकार भी इस समस्या को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

इसी क्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है। यह विद्यालय मुख्य रूप से अनु.जा., अनु.जन.जा. व पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए है जिससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली बालिकाओं को भी शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सकें। इस योजना में केंद्र सरकार का 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत का योगदान होता है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को जल, स्वछता और साफ सफाई के बेहतर सुविधाआं को उपलब्ध करने और इनके उपयोग के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए यह परियोजना वाटर एड और नेशनल स्टोक एक्स्चेंज (एन.एस.ई.) के सहयोग से चलाई जा रही है।

परियोजना का उद्देश्य :

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में जल, स्वछता व स्वास्थ्य को लेकर एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम 'प्रज्वला' है। इस योजना को चलाये जाने का मुख्य उद्देश्य है कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकाओं की जल, स्वछता व स्वास्थ्य से सम्बंधित सर्वांगीण जानकारी प्रदान करना।

इस परियोजना के अंतर्गत मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम किया जाता है। इसमें हार्डवेयर के अंतर्गत जल को प्राप्त करने के मूलभूत श्रोत, गंदे जल का निस्तारण, पानी के श्रोत और निस्तारण से संबंधित स्थिति का पता लगाना, यदि स्थिति ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने की व्यवस्था करना शामिल है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इस सभी श्रोतों का सही प्रकार से इस्तेमाल करने की जानकारी देना तथा बालिकाओं को स्वछता व स्वास्थ्य संबंधी

जागरूकता बढ़ाना है।

कार्यक्षेत्र :

क्रं.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम
1.	सिवनी	लखनादौन, छपारा, हरई, अमरवाड़ा
2.	शहडोल	बुढर, सोहागपुर, पाली, गोहपारु
3.	अनूपपुर	कोतमा, पुष्पराजगढ़, जैतहारी, अनूपपुर
4.	उमरिया	मानपुर, बधओगढ़, जयसिंहनगर, व्यौहारी
5	छिंदवाडा	तामिया, परसिया, जुन्नारदेव
6	खंडवा	खालवा, पंधाना, हरसूद, बलडी

इस परियोजना के अन्तर्गत महात्मा गाँधी सेवा आश्रम के द्वारा 6 जिलों (उमरिया, शहडोल, सिवनी, छिंदवाडा, खंडवा और अनुपपुर) के 23 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में 3250 बालिकाओं में जल, स्वछता और साफ सफाई से संबंधित व्यवहार परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है।

मुख्य हस्तक्षेप या गतिविधियाँ :

प्रज्वला परियोजना के अंतर्गत महात्मा गाँधी सेवा आश्रम की ओर से सभी 6 जिलों में स्थित कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का भ्रमण किया गया। छात्रावास अधीक्षिका, प्राचार्य तथा बालिकाओं से मुद्दा आधारित बातचीत की गई।

छात्रावास अधीक्षिका एवं प्राचार्य से बातचीत :

छात्रावास अधीक्षिका एवं प्राचार्य से संबंधित छात्रावास के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। बातचीत के क्रम में यह जानने का प्रयास किया गया कि छात्रावास में बालिकाओं की संख्या कितनी है, जल, स्वछता और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, शौचालय अथवा नल में पानी की स्थिति क्या है,पानी की व्यवस्था पाईप से है या दूर से लाना पड़ता है, हाथ धोने का स्थान कहां और कैसा है, नल खराब तो नहीं है, पानी व्यर्थ तो बर्बाद नहीं हो रहा है, शौचालयों की स्वच्छता और बालिकाओं के स्वास्थ्य की स्थिति, भोजन पकाने का स्थान, ठोस तथा तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त की गई एवं प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन भी किया गया। इसके अलावा यह जानने का प्रयास भी किया गया कि क्या इन मुद्दों से संबंधित बालिकाओं को कोई और सुविधा मिल रही है।कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के स्टाफ के बारे में जानने का प्रयास किया गया।यह भी जानने की कोशिश की गई कि बालिकाओं की दिनचर्या क्या है ताकि खाली समय में बालिकाओं के साथ बेहतर काम किया जा सके।

बालिकाओं से बातचीत :

छात्रावास के भ्रमण के दौरान वहां निवासरत् बालिकाओं से बातचीत की गई। सभी बालिकायें कक्षा 6 से 8 तक की थीं। यहाँ इनके भोजन, पढ़ाई, खाना और रहने की व्यवस्था की गई है। इन बालिकाओं से मुख्या रूप से जिन मुद्दों

पर बात की गई वे निम्न हैं–

- बालिकाओं में जल ,स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का स्तर।
- बालिकाओंके शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके व्यक्तित्व विकास, उनमें होने वाले बदलाव तथा स्वच्छता के संबंध में प्रोत्साहन संबंधी चर्चा।
- बालिकाओ में माहवारी के दौरान व्यक्तिगत सफाई।
- माहवारी में एनीमिया जैसी बीमारी से बचने के लिए पोषक आहार पर चर्चा।
- सैनिटरी पैड या कपड़ा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित चर्चा।
- किशोरावस्था व उनमें होने वाले बदलाव की जानकारी।
- सामाजिक मान्यताओ व माहवारी से संबंधित समाजिक भ्रान्तियों पर चर्चा व बालिकाओं के विचार जानने का प्रयास।
- हाथ धोने का स्वच्छता व स्वास्थ्य से संबंध और हाथ धोने का सही तरीका।

परियोजना की उपलब्धियाँ :

संस्था के द्वारा कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के वास एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन से संबंधितनिर्धारित प्रथम चरण के कुल 12 सत्र समाप्त हो चूके हैं। इन विद्यालयों में बाल कैबिनेट का गठन भी हो चुका है।

उपरोक्त 12 सत्र के सफल संचालन के बाद संबंधित विद्यालय की अधीक्षिका औए सहायक अधीक्षिका के द्वारा दिये गये फीडबैक से पता चला है कि सत्र–संचालन के बाद बालिकाओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है और बालिकायें माहवारी के समय भी स्वच्छता का ध्यान रखने लगी हैं।

6. ''सहभागी सीख प्रक्रिया'' से कुपोषण मुक्ति अभियान, जिला-बड़वानी

परियोजना की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य :

कुपोषण एक देशव्यापी समस्या है और मध्यप्रदेश के पिछड़े जिलों में से एक बड़वानी भी इससे अछूता नहीं है। बड़वानी जिला में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर भी काफी अधिक है जिसका सबसे बड़ा कारण माता एवं शिशु द्वारा एकजूट (रांची, झारखण्ड), यूनिसेफ तथा एकीकृत महिला एवं बाल विकास के साथ मिलकर पी.एल.ए. कार्यक्रम की शुरूआत की गई।

परियोजना का उद्देश्य मातृत्व एवं शिशु पोषण में सुधार करना है। इसके लिये समुदाय की सहाभागिता के द्वारा मातृत्व एवं शिशु पोषण में कमी के कारणों की खोजकर उनको दूर करने का प्रयास करना है। समुदाय स्वयं अपनी समस्याओं को खोज कर उसका निराकरण कर सके इसके लिये पी.एल.ए. पद्धति को अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत सहभागी प्रक्रिया द्वारा सीखना एवं उस सीख एवं अनुभवों के आधार पर योजना बनाकर उसे लागू करना है। पी.एल.ए. प्रक्रिया के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समुदाय के साथ मिलकर उनकी समस्या को जानना, समस्याओं के संभावित कारणों को खोज करना और उनको दूर करने के उपाय ढुढ़ना एक कारगर प्रक्रिया साबित हुआ है। इसके लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पी.एल.ए. प्रक्रिया पर समझ व दक्षता विकसित करने का काम परियोजना के तहत किया जा रहा है। पी.एल.ए. सहभागी सीख प्रक्रिया को चार चरणों मे बांटा गया है। प्रत्येक चार चरण में चार-चार बैठकें प्रस्तावित हैं-

पहला चरण : समस्याओं की पहचान करना।

दुसरा चरण : समस्याओं का समाधान ढुंढना, रणनीति बनाना और जिम्मेदारियों का बंटवारा करना।

तीसरा चरण : रणनीतियों को लागू करना।

चौथा चरण : रणनीतियों एवं किये गये प्रयासों का मुल्यांकन करना।

पी.एल.ए. बैठकों के लिये आवश्यक है कि–

- वंचित एवं कमजोर वर्ग अधिक संख्या में भाग लें।
- बैठकों का दिन एवं समय समुदाय के लोगों की सुविधानुसार तय हो या बदला जा सके।
- बैठक किसी खुले स्थान या पेड़ के नीचे आयोजित हो जिसमें सभी लोग सहभागिता कर सकें।

परियोजना का कार्यक्षेत्र एवं लक्ष्य समूह :

परियोजना का कार्यक्षेत्र बड़वानी जिले का राजपूर ब्लाक है जिसमें महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आने वाली सभी 340 आंगनबाड़ी केन्द्रों को शामिल किया गया है। राजपूर ब्लाक में प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए 12 बेच का निर्धारण किया गया जिसमें सेक्टर के अनुसार सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण में उपस्थित होना निश्चित किया गया। प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में एकजूट और महात्मा गांधी सेवा आश्रम के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग से सेक्टर सुपरवाइजर तथा पिरामल फाउन्डेशन व ग्रामीण आजीविका मिशन से गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में शामिल किया गया। इस हेतू जिला एवं ब्लॉक कार्यालय से अनुमति पत्र प्राप्त कर बेच का निर्धारण किया गया।

गतिविधि	संख्या	प्रतिभागी संख्या
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	31
सहजकर्ता प्रशिक्षण	12	294
ग्रामस्तरीय बैंठक	198	7008
सेक्टर बैठक	24	600

परियोजना की मुख्य गतिविधियां :

- मास्टर ट्रेनर का चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण।
- आंगनवाडी कार्यकर्ता का चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण ।
- ग्राम स्तर पर सहजकर्ता द्वारा समुदाय के साथ पी.एल.ए. बैठकें।
- जिला एवं ब्लॉक स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय एवंकार्यक्रम की जानकारी साझा करना।

7. वंचित समुदाय का सशक्तिकरण

वंचित समूदायों के भूमि अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह परियोजना देश के छः राज्यों, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िसा, असमऔरमणिपुर में महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा, मुरैना के द्वारा पिछले एक दशक से भी अधिक समय से चलाया जा रहा है।यह परियोजना अन्य परियोजनाओं से इस मायने मे भिन्न है कि यह दीर्धकालीन संस्थागत संबंधों को स्थापित करते हुये एक मजबूत और न्यायपूर्ण नागर समाज के निर्माण के लिय माहौल और ढांचा तैयार करने में मदद करता है। अतः परियोजना के निर्धारित कार्यक्रमों को संचालित कर देना तथा परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त करलेना भरहीं इसका उद्देश्य नहीं है बल्कि लम्बे समय तक आवश्यक और रणनीतिगत सहयोग कर संस्था तथा लक्ष्य समूहों का सर्वांगीण विकास ही इस परियोजना के मजबूत संबंधों का आधार है।

परियोजना के उद्देश्य :

''मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िसा, असम और मणिपुर के 775 गांवों के लक्ष्य समूहों (आदिवासी, दलित, घुमन्तु समुदाय, भूमिहीनों तथा वंचित वर्ग के लोगों) को सशक्त बनाना ताकि संबंधित राज्य के वन अधिकार अधिनियम, राजस्व अधिनियम तथा आवासीय भूमि अधिकार के तहत वे अपने दावे/आवेदन लगा सकें और भूमि और जीविकोपार्जन के अधिकार प्राप्त कर सकें।''

पिछले वर्ष की भांति इस वित्तीय वर्ष में भी इस परियोजना के तहत 6 राज्यों, 20 जिलों, 37 ब्लॉकों तथा 776 गांवों में मुख्यतः सहरिया, बैगा, गोंड, पण्डो, सबर, दलित, घुमन्तु आदि जनजातियों/समुदायों के साथ सघन रुप से काम किया जा रहा है।

परियोजना का कार्यक्षेत्र :

राज्य	जिला	ब्लॉक	गाँवों की संख्या
मध्यप्रदेश	4	11	255
उत्तरप्रदेश	2	6	124
ओडिसा	2	4	122
छत्तीसगढ़	3	4	115
मणीपुर	3	4	60
असम	6	8	100
6	20	37	776

कार्यक्षेत्र के गांवों में आवश्यकतानुसार तीन प्रकार के कार्यो को संचालित किया जा रहा है –

- **आवास एवं कृषि भूमि का हक प्राप्त करना :**

- वन अधिकार अधिनियम, राजस्व अधिनियम तथा आवासीय भूमि अधिकार के तहत दावे/आवेदन दर्जकर भूमि अधिकार सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के नाम से व्यक्तिगत/संयुक्त भूमि अधिकार दिलाना।
- वन अधिकार अधिनियम के तहत दावा से कम भूमि प्राप्त होने के खिलाफ ग्राम – सभा को विरोध प्रस्ताव लाने के लिये प्रोत्साहित करना और न्यायालय में जनहित याचिका दायर करना।

- वन अधिकार अधिनियम के तहत सामूदायिक दावा लगाना तथा ऐसे गांवों को जिसे शहरी क्षेत्र में जोड़ लिया गया है, के अधिकार दिलाने का प्रयास करना।
- असम में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिये स्थाई पुर्नवास नीति तथा मणिपुर में आवास नीति बनाने के लिये सरकार पर दबाव बनाना।
- उत्तर प्रदेश में सहरिया समूदाय को अनुसूचित जनजाति तथा छत्तीसगढ़ के पण्डों समुदाय को आदिम जाति का दर्जा प्रदान कराने का प्रयास करना ताकि उन्हें भूमि अधिकार प्राप्त हो सके।
- सरकार की गरीब विरोधी नीति और कानूनों के खिलाफ आवाज उठाना।
- एक साथ मिलकर भूमि अधिकार प्राप्त करने के क्रम में स्थानीय आर्थिक संसाधन जैसे अनाज कोष और ग्राम कोष इकट्ठा करना।

प्राप्त भूमि पर पारम्परिक खेती करना :

- पारम्परिक खेती का प्रशिक्षण देकर लोगों को जैविक खेती करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- शुरुआती दौर में रसायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग कम करना।
- पारम्परिक बीज बैंक बनाना।

जल संरक्षण के लिये श्रमदान करना

- छोटे–छोटे जल संरचनाओं की मरम्मत और सफाई करना।
- आवश्यकतानुसार जल संरक्षण के लिये नयी संरचना बनाना।
- वृक्षारोपण कर जल संवर्धन का प्रयास करना और मिट्टी के कटाव को रोकना

परियोजना क्षेत्रों में श्रमदान की झलकियाँ

श्यामपुर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) में श्रमदान कार्य

बिचलधाटी, सरगुजा छत्तीसगढ़ में श्रमदान

श्यामपुर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) में श्रमदान कार्य

बालूबाजी, कालाहांडी, उड़ीसा में श्रमदान

श्यामपुर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) में श्रमदान से निर्मित बाँध

जुआड़ी अम्बा, उड़ीसा में श्रमदान

• गतिविधियाँ :

कुछ विशेष कार्यक्रम और गतिविधियां की गई जिसे निम्न तालिका में देखा जा सकता है–

कार्यक्रम का नाम	स्थान	आयोजित कार्यक्रम	प्रतिभागी संख्या
कानूनी प्रशिक्षण	वारंगल, तेलंगाना, दिल्ली	3	30
क्षेत्रीय भूमि सम्मेलन	तिरुअनन्तपुरम, केरल, नईदिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता	4	238
राष्ट्रीय भूमि सम्मेलन	ग्वालियर, म.प्र.	11	6043
जनसुनवाई	इम्फाल, मणीपुर, ओरछा, झांसी, लखेश्वरी, ग्वालियर भितरवार, मुरार, ग्वालियर, बदरवास, शिवपुरी, रामनगर अशोकनगर, बदरवास, अशोकनगर, मुंगावली अशोकनगर, म.प्र.,झांसी, उ.प्र.	13	3303
जन वकालत कैम्प	धेमाजी, असम, विशुनपुर, मणीपुर, इम्फाल, मणीपुर	3	176
श्रमदान शिविर	श्यामपुर, शिवपुरी, म.प्र., जुआड़ीअम्बा, खुर्धा, ओड़िसा बडकाबहरा, कोरबा, छत्तीसगढ़, छिन्दवार, कोरबा		
	छत्तीसगढ़, बिछलघाटी, सरगुजा, म.प्र., धुबरी, असम	6	399
महिला सम्मेलन	ओड़िसा, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, अशोकनगर , ग्वालियर और शिवपुरी म.प्र.	5	1199
जैविक खेती प्रशिक्षण	भोपाल, कामरुप, धेमाजी, असम, ग्वालियर, गुना	5	526
पदयात्रा	ग्वालियर, म.प्र.	2	1765

परियोजना से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें :

परम्परागत पंचायत	इस वर्ष उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेशमें 29 पारम्परिक पंचायतें आयोजित की गई जिसमें 3189 लोगों ने भाग लिया।
मानवाधिकार दिवस	10 दिसम्बर 2018 को मुंगावली और चंदेरी में लोगों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन तहसीलदार और कलेक्टर को दिया गया।
अन्नदान महादान	इस वर्ष अन्नदान महादान कार्यक्रम के तहत परियोजना के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र से 135.32 क्विंटल अनाज इकट्ठा किया गया।

कार्यक्षेत्र में नियमानुसार चलने वाली ग्राम इकाई की मासिक बैठक, अनाजकोश, ग्रामकोश संग्रहण के अलावा

परियोजना के परिणाम :

- वर्ष 2018–19 में वनअधिकार अधिनियम, राजस्व अधिनियम तथा आवासीय भूमिअधिकार के तहत कुल 8838 आवेदन दर्ज किये गये।
- कुल दर्ज दावों में से 2778 परिवारों को भूमि अधिकार प्राप्त हुआ जिसमें से 1193 भूमि दस्तावेजों पर महिलाओं का नाम दर्ज है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में परियोजना के छः गांवों में जल संरक्षण और जल संबर्द्धन का काम किया गया जिससे लोगों और पशुओं को पीने के पानी के अलावा किचन गार्डन और खेती के लिये भी पानी उपलब्ध हुआ है।
- परियोजना के कार्यक्षेत्र में कुल 135.32 क्विंटल अनाज इकट्ठा किया गया।
- असम राज्य में बाढ़ के दौरान राहत कार्य भी चलाये गये।
- पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यकर्ताओं के लिये एक विशेष प्रकार की डायरी बनाई गई ताकि कार्यकर्ता अपनी योजना और किये गये कार्यो के बारे में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की जानकारियों को

परियोजना क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियाँ

8. मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के वंचित समुदाय के लिए टिकाउपन आजीविका सुनिश्चित करना

1. परियोजना का परिचय :

महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा भूमि अधिकार और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार अभियान के अंतर्गत हजारों परिवारों को राजस्व भूमि का पट्टा मिला है तो हजारों परिवारों को वन अधिकारों की मान्यता कानून के अंतर्गत वन भूमि का अधिकार हासिल हुआ है। जिन क्षेत्रों में भूमि प्राप्त हुई है वहां पर वंचित समुदाय के किसानों की बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने के लिए क्रिश्चियन एड संस्था के सहयोग से दो राज्यों क्रमशः मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में वंचित समुदाय विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति के बीच पलायन और गरीबी को दूर करने तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए टिकाउपन आजीविका सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कृषि और वनोपज आधारित गतिविधियों को मजबूत कर वंचित समुदाय के परिवारों के आर्थिक स्वावलम्बन के तथा टिकाउपन आजीविका के निर्माण के लिए यह परियोजना संचालित की जा रही है।

2. भौगोलिक कार्यक्षेत्र :

राज्य	सम्मिलित जिले	गाँव की संख्या	लक्ष्य परिवार संख्या
मध्यप्रदेश	मुरैना, श्योपुर, सागर, रायसेन, सीहोर जबलपुर कटनी, दमोह उमरिया	34	1700
छत्तीसगढ	सरगुजा	6	300
योग	10	40	2000

3. परियोजना के उद्देश्य :

परियोजना के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- सरकारी तथा गैर सरकारी आजीविका की योजनाओं को हासिल करना।
- वंचित समुदाय के लिए टिकाउपन आजीविका का निर्माण।
- आर्थिक उपक्रम ;इंटरप्राइजेजद्ध का विकास।

2. परियोजना की गतिविधियाँ :

- **दस्तावेजीकरण और अध्ययन :** परियोजना के प्रारंभ में 40 गावों के बीच 14 गांव का सर्वे किया गया और उसके आंकडों को कम्पयूटर में फीड कराया गया है। जो शेष सर्वे से रह गये हैं वहां पर काम चल रहा है।
- समुदाय के बीच गठित स्वयं सहायता समूह की स्थिति का विश्लेषण तथा संभावित उपक्रम के लिए अध्ययन, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी स्तर पर मोड्यूल तैयार किया गया है।
- **स्वयं सहायता समूह का गठन और मजबूती तथा आर्थिक गतिविधियों का संचालन :** वंचित समुदाय के बीच महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से सशक्त करने के लिए 200 महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया और इनमें से 140 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण दिया गया।
- **आर्थिक उपक्रम, इंटरप्राइजेजद्ध का विकास :** महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा कार्य करने के दौरान अनुभव हुआ कि किसान परिवारों के आर्थिक रूप से स्वावलम्बन के लिए किसान उत्पादक समूह बनाया जाना चाहिए। इस सोच के अनुरूप इक्वीटी, सालिडेरिटी एण्ड जस्टिस किसान उत्पादक प्राइवेट कम्पनी का गठन किया गया है। इस कम्पनी के माध्यम से शहद, सरसों तेल, अरहर दाल और मसाला का विपणन का कार्य किया जा रहा है।
- **शहद के विपणन के लिए प्रभावशाली पैकेजिंग :** ईएसजे किसान उत्पादक कम्पनी के माध्यम से किये जाने वाले शहद तथा सरसों तेल की पैकेजिंग के लिए सीसे और प्लास्टिक का बोतल की व्यवस्था की गयी। इसके साथ ही उसकी पैकेजिंग रैपर का आधुनिक तरीके से डिजायन तैयार किया गया।

- **तेल घानी इकाई की स्थापना :** परंपरागत तरीके तेल घानी से तेल बीजों से तेल निकालकर उसका विपणन करने के लिए तेलघानी इकाई की स्थापना महात्मा गांधी सेवा आश्रम में किया गया है। चम्बल क्षेत्र सरसों बीज का उत्पादक क्षेत्र है और बाजार में तेलघानी का जैविक शुद्व तेल की मांग अधिक है। इसकी संभावनाओं को देखते हुए महिला किसानों का समूह गठित करना और जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। जिससे कि जैविक सरसों के बीज के उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित किया जा सके तथा शुद्व सरसो तथा अलसी के तेलघानी का तेल का उत्पादन और विपणन किया जा रहा है।

- **तेल का उत्पादन और विपणन :**

इस वर्ष सरसों तेल और अलसी तेल का उत्पादन निम्न प्रकार किया गया :

बीज का नाम	बीज की मात्रा किग्रा	तेल का उत्पादन किग्रा.	
सरसों	4025	805	कोल्हू
		463	स्पेलर
		2645	खली
अलसी	25	8.200	कोल्हू
		16.30	खली

- ✓ कोल्हू से निकाला गया सरसों का तेल स्पेलर से निकाले गये तेल की अपेक्षा अधिक शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। यह तेल औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है, एक प्रकार से यह एंटीसेप्टिक तेल भी होता है।
- ✓ अलसी का प्रचलन बहुत ही पारंपरिक है किंतु उत्पादन नहीं होने के कारण एक तरह से यह चलन में नहीं रह गया है, जबकि अलसी में ओमेगा 3 फेटी एसिड पाया जाता है। यह कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए अलसी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी समाज के एक वर्ग विशेष में अलसी को भून कर खाने का प्रचलन अधिक है। इसकी बाजार की संभावना को देखते हुए इसका व्यवसाय किये जाने की रणनीति बनाई गयी है। ✓ संस्था के स्टॉक मे अभी 340 लीटर कोल्हू सरसों तेल, 313 लीटर स्पेलर सरसो तेल तथा 100 कुंतल खली है।

- **कार्यकर्ता तथा आदिवासी किसानों की जैविक खेती पर क्षमता विकास :** परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर पर एक प्रशिक्षण का आयोजन जनवरी 2019 में सागर में किया गया, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों ने जैविक खेती तथा बहुमंजलीय खेती अर्थात चार स्तरीय खेती की तकनीकी को सीखा। इस प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ समुदाय से चयनित कुछ लोगों ने भागीदारी की।

- **लक्ष्य समुदाय का जैविक और चार स्तरीय खेती पर क्षमता विकास :** लक्ष्य समुदाय के किसानों का जैविक और चार स्तरीय खेती पर क्षमता बढानें के लिए चार एक दिवसीय शिविर आयोजित किये गये। इसमें रायसेन, सीहोर में दो, उमरिया में एक तथा जबलपुर में एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों की खेती की लागत को कम करना तथा कम्पोस्ट खाद का निर्माण, नीमास्त्र तथा अमृत खाद को लेकर किसानों की रूचि को जागृत करना तथा उनको प्रशिक्षित करना था।

- **मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण :** मधुमक्खी पालने के लिए जौरा तथा उसके आस पास के गांवो नरहेला, सांकरा तथा जौरा के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद भागीदारों को राज्य खादी ग्रामोद्योग के द्वारा हनी मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पेटी का वितरण हितग्राही अंशदान के अंतर्गत किया गया। 75 हितग्राहियों को 750 पेटी तथा शहद निकालने और मधुमक्खी से बचाव के लिए औजार भी दिये गये जिसकी प्रत्यक्ष लागत लगभग 40 लाख रूपये होता है।

- **मतदाता जागरूकता अभियान :** मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कार्यक्षेत्र के जिलों में समुदाय के बीच मतदाता जागरूकता के लिए 8 बैठकें आयोजित की गयीं जिसमें लगभग 1100 मतदाताओं ने भागीदारी की तथा मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अपील की गयी। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि चुनाव के दौरान प्रयुक्त होने वाले शराब और नोट के भ्रष्टाचार को बंद किया जाये।

9. Regional Nutrition Program - Sheopur (M.P.)

1. Background of Project :

Sheopur district of Madhya Pradesh is famous as the 'Ethiopia of India'. The reason for this repute is malnutrition. It is also challenging to combat this pitiable situation. Most of the families belongto the tribes and due to the lack of nutritious food they could not provide nutritious food or at least 2 time meals to their kids and women even after 70 years of Independence of our country. MGSA started a campaign 3 years ago to combat this situation among the Sahariya tribes in Karahal block of Sheopur with the help of WHH. As a result situation is now in control and rating to provide services from government to the community has improved for better. Now, MGSA is trying to develop the Nutrition Smart Village for sustainable development in food security and nutrition among the most deprived community in the State.

2. Goal and Objectives of the Project :

GOAL : Improvement in the food and nutrition situation of vulnerable groups, specifically women of reproductive age and young children through,

Promotion of a multi sector approach for nutrition smart villages

OBJECTIVES : Followings are the objectives of the project to reach the goal:

- ✓ **Overall Objectives (Impact)** : To contribute to food and nutrition security (SDG 2) amongst women of reproductive age and young children from vulnerable and food insecure families in 50 villages in District Sheopur.
- ✓ **Project Purpose (Outcome) :** Under-nutrition in target areas is reduced through improved care practices and dietary diversity
  - ❖ Increased Dietary Diversity among the women of reproductive age (15-49

years).

- Improvement in Minimum Acceptable Diet (MAD) for children in the age group of 6-23 months.

3. Result wise Activities and Strategy :

Following are the result wise plan activities for the project

Result 1 : Knowledge, awareness and practices of target households on diet diversity, maternal-child care, nutrition sensitive agriculture and WASH are improved.

I. Baseline & end line study

II. Adapt needs assessment to local situation and needs assessment; localization of LANN PLA manual

III. Training of Trainers of NGO Staff and Master Trainers on LANN PLA

IV. Conduct LANN PLA Cycles with the communities in 100 villages

V. Development of Integrated Farming Systems

Result 2 : Dietary diversity for households, particularly women and children, is increased through promotion of nutrition sensitive and climate smart agriculture

I. Promote Farmer Field Schools

II. Development of Integrated Farming Systems

III. Support nutrition gardens for families with moderately malnourished children

Result 3 : Community based organizations, village level institutions and local government bodies in target areas are capacitated to access government programmes and entitlements

I. Strengthen community institutions for better nutrition monitoring

II. Develop nutrition sensitive climate smart micro-plans and support the implementation pilot interventions on WASH

III. Finalize process manual and training kit on nutrition sensitive micro-planning

IV. Train NGO staff and master trainers on micro planning

V. Develop nutrition sensitive development and adaptation micro-plans

VI. Support entry point activities on WASH

Result 4 : Enhanced access of government and development actors to data, evidence, information and knowledge on replicable models to guide multi-sectoral programming towards better nutrition.

I. Documentation of good practices- video film

II. Create a collaboration platform with government and civil society for district and sub district level nutrition sensitive micro-planning - Capacitate and support local

government officials on participatory, nutrition sensitive planning & Establish a collaboration framework for the effective implementation of micro-plans

III A regional platform for Civil Society Organizations developed for exchange of knowledge, transfer of good practices and advocacy at the national and SAARC level- (2 in India, 2 in Nepal and 1 in Bangladesh)

IV. Conduct advocacy workshops at local and national level- 28 advocacy workshops, 4 by each of the seven partners will be conducted- two at sub district level, and one each at district and national level

STRATEGY :

- Strengthen a multi-stakeholder framework through convergence, coordination and sensitization for improved nutrition outcomes.
- Initiate nutrition education and behavioural change through Participatory Learning and Action (PLA) + LANN
- Facilitate Model Nutri-smart 50 villages**.**
- Increased access to Government entitlements/ programs through raised awareness, community-based planning and monitoring of public services.

4. Intervention area and community

District	**Block**	**Numberof villages**
Sheopur	Karaha	l50

Details	**Number**	**Details**	**Number**
House holds	8988	Population	43424
Male Population	22549	Female population	20875
Adolescent Girls	2137	Pregnant Women	802
Lactating women	859	Children (6 month to 3 Yrs)	2869
Children (3 to 6 Yrs)	2871		

5. Activities and Achievements :

5.1 Identification and Surveyed : At the beginning of the project, secondary data from NSSO and ICDS collected and analyzed for the identification of challenges and obstacles in nutrition smart village as well as number of malnourished children, which are followings:

5.1.1 Population : There are 7246 Households having 36663 population including Male 18806 (51.21%) and Female 17857 (48.70%). Cast wise distribution show that 0.952% house hold falls under General Category, 18.53% of other backward classes, 5.93% are Scheduled caste and 74.57% of total population belongs to Saharia primitive Tribe.

5.1.2 3409 families are dependent on agriculture as livelihood. 1386 families fall under APL, 2444 under BPL, 2024 AYY. 6393 families are living in kuchaa houses. There are 177 Self Help groups are active.

5.1.3 **Agriculture :** 9775.29 hectares of land being used for agriculture out of that only 6957.6 hectares is irrigated and 4466.69 hectares is non-irrigated land. Sources of irrigation available are 30 ponds, 111 well, 790 tube well, 3 river and a canal.

5.1.4 **Livestock:** Total Number of milking animals are: cow 4197, buffalo 1599, goat 9870.

5.1.5 **Water Sanitation and Health :** Total number of toilets built in the region – 5766. Number of families which use the toilets are 1380. There are 24 public distribution shops, 2125 families have adequate land for the nutrition garden and there are 392 fruit trees in the region.

5.1.6 **Malnourished Children :** There are 4721 children from the age group of 0 to 5 years, 3224 children are normal, 1075 are MAM and 381 are SAM.

5.1.7 **School Institution :** There are 49 Primary School (boys- 2019 and girls – 1939), 21 middle school (boys- 916 and girls – 735), and 3 high school (boys- 80 and girls – 50)

5.1.8 **Anganwadi Centers :** Total AWC 82 (70 Main and 12 Mini), GAK 26, Sub health Center 12, ANM 21and ASHA 40.

5.2 **Inception workshop :** AState Level Inception Workshop was organized for the orientation of the team member at Bhopal on December 7-8, 2018. This workshop was organized and facilitated by Ms. Pratibha Srivastava, State Coordinator, WHH, India. The objective of the workshop was to share the concept of multi-sectoral approach to the partners, to develop understanding on strategic measures of the project and to develop common understanding among the partners. All the participants were involved in sessions which were based on participatory mode. Participants succeeded in developing a clear understanding on project-based topics and also had an opportunity to develop understanding with the partner implementation team in Madhya Pradesh. Various exercises conducted during the session helped participants to get customized to various field-based situations.

5.3 **Capacity building of team member :** A five days project exposure visit for the partner agencies under Regional Nutrition Program was organized by Welthungerhilfe, India at Deoghar 17th to 21st Dec'18. 4 team members from MGSA Sheopur, had participated in 5 days learning program of Nutrition Smart

Village Project. The objective of exposure visit was to acquaint project staff about the project and to understand the important aspects of conducting a Nutrition Camp, LANN PLA meetings, Keyhole kitchen garden, WASH and SIFS and hands on AKVO Flow. In order to observe and learn effective implementation strategies of NSV project, Team MGSA visited intervention areas (Singhini, Parasboni, Jalahara, Dhorwa, Doodhitand, Amjo, Baigabad, Chandana and Jhanjhi villages) of Pravah and Abhivyakti Foundation NGO, Deoghar. This exposure visit was organized and facilitated under wise supervision and esteemed presence of Ms. Pratibha Srivastava and technical part of project learning was headed by Ms. Shweta Banerjee State Coordinator, WHH, Jharkhand, India. A local NGO Pravah being partner of WHH provided lodging support and facilitated field visits. All the Partner organizations of WHH in India, Nepal & Bangladesh had attended this learning exposure visit. And it helped us to understand and plan the project activities implementation strategies and team work

5.4 **District Level Workshop :** The objective of the workshop was to share the concept of multisectoral approach to the partners and to develop understanding on strategic measures of the project as well as develop common understanding among the various departments of Government. More than 60 Government officers including District Collector were involved in sessions which were based participative mode. The workshop achieved its stated goal through extensive discussion on the risks and benefits of partnerships with different departments. Officers from different departments identified and agreed on common ground for moving forward with a direction of action.

5.5 **Volunteer's Orientation Program :** 50 volunteers were identified and orientated from each village in the project area on Regional Nutrition Program. Their understanding about on various activities of Regional Nutrition Program increased and their roles and responsibilities were identified through mutual understanding and volunteerism.

5.6 **CSAM Training-Bhopal** : A two days training program on CSAM organized with ICDS Supervisors, NRP and FaNS Team Members. The Community-Based Management of Acute Malnutrition (CMAM) approach enables community volunteers to identify and initiate treatment for children with acute malnutrition before they become seriously ill. Caregivers provide treatment for the majority of children with severe acute malnutrition in the home using Ready-to-Use-Therapeutic Foods (RUTF) and routine medical care. When necessary, severely malnourished children who have medical complications or lack an appetite are

referred to in-patient facilities for more intensive treatment. CMAM programmes also work to integrate treatment with a variety of other longer-term interventions. These are designed to reduce the incidence of malnutrition and improve public health and food security in a sustainable manner.

5.7 **Capacity building for collection of Data**– A training was organized for collecting data through AKVO FLOW application and it's analysis where 12 members were participated and learned and practiced about Akvo flow app on smart phones, using dashboard and data analysis. This helped to finalize the questionnaires and plans for data collection

5.8 **Sustainable integrated farming Systems Workshop –Joura:** 7 team members of RNP and 6 Farmer volunteers from Block Karahal participated in 2 days SIFS workshop organized in Mahatama Gandhi Sewa Ashram, Joura. They learned and practiced about the integrated farming systems in low rainfall areas. Water harvesting structures in the form of small farm ponds or community large ponds are constructed and integrated with fishery, duckery, etc. Gulley plugging is to be resorted to wherever needed. Topo-sequential cropping involving agro forestry in top portion, horti-pastoral crops in the middle and agricultural crops like rice, maize/popcorn, soybean, groundnut etc. are to be grown in lower portion of the land for effective management of land and water resources. It is also possible to integrate different components of ecosystem (land, water, plant species etc.) to obtain sustained production from rainfed and degraded lands to check natural hazards like drought. Integrated farming system is a commonly and broadly used word to explain a more integrated approach to farming as compared to monoculture approaches.

5.9 **Baseline Survey** : After the training on collecting base line data for the project, a

12 member team from the BSS, Bhopal collected the data of 326 children from the intervention area.

6. Achievements :

a. Capacity Building: Team Members, Volunteers, ICDS Supervisors and Anganwadi workers (70 Volunteers, 7 team members of RNP, 4 team members from FaNS, 40 ICDS Supervisors, 80 ICDS Anganwadi workers, 60 volunteers and 5000 community members from 50 villages) were capacitated about the project, activities and role and responsibilities and plan of action prepared and sustainable integrated farming systems.

b. Engagement of different stakeholders : Entire line department with food security and nutrition issues such as WCD, Health, Horticulture, Agriculture, MNREGA, Forest, Animal Husbandry, PHED, NABARD, Fisheries and Tribal affairs departments were engaged and a common understanding developed to combat the malnutrition situation and nutrition smart village for the sustainable development of the community to access the nutritious foods for their families and strengthen the service delivery systems.

c. Identification and Orientation of Volunteers in 50 villages : 50 selected youths from each village were oriented about the intervention at village level to develop the nutritious smart village, Collecting Village level Information, Counseling session at HH Level and group level, Attended training on Training on SIFS and CSAM, Follow up meetings with AWW's, Assist ANM in Vaccination of Children, Community mobilization in promotion of Local food and organic manure and organize awareness Session on Wash Practices at village level.

d. Development of nutrition garden and sustainable integrated farming system : This project has been develop the 42 nutrition garden and selected 50 farms to develop the models of SIFS.

7. Further plan of action:

- ✓ Nutrition Education and development of Community Model through PLA + LANN
- ✓ Partnerships and Collaborations Community, NGO's and Govt. Departments
- ✓ Develop sustainable Approach and multisectoral approach and build traditional knowledge
- ✓ Development of 50 villages Nutri smart by capacity Building of AWW/ASHA /Krishi Mitra, Sustainable Integrated farming and Nutrition camps, village Micro planning towards nutrition must be shared to give the ideas to the participants.
- ✓ Organize Nutrition camp-15 Days nutrition and counseling camp
- ✓ Farm school for sustainable integrated farming system
- ✓ Develop the nutrition garden in 750 households in 50 villages

10. "TRAPPED IN COTTON" PROJECT, DHAR (M. P.)

1. Background of the Project :

As per the Census 2011, in terms of monthly income of highest earning household member, majority in the Madhya Pradesh (nearly 84 per cent) earn less than INR 5000 per month, followed by those between INR 5000-10,000 (11.3 per cent) and lastly, only 5.2 per cent earn more than INR 10,000. The figure is even lower for tribal population with over 90 per cent households with monthly income of highest earning household member less than INR 5000. Due to their marginalized status and lack of viable alternatives, many families have no choice but to send their children to work. As a result, the percentage of out-of-school children (age 6-14) has increased between 2014 and 2016 from 3.4 per cent to 4.4 per cent in Madhya Pradesh. Child labour is found to be rampant in Dhar where around 58.5 percent children reported working as their primary occupation. Approximately 32 percent of these children are in the age group of 7-14 years. Those who reported to be attending schools also stated engaging in similar kind of income generating activities as their out of school counterparts do. There are no fixed hours for work in the field. The working hours range from 2 to 12 hours on a daily basis. Girls also reported to be working for similar hours like boys in the field. MGSA is working in Dhar district of Madhya Pradesh on child labour issue with the support of "SAVE THE CHILDREN' for child labour in cotton farms.

"Trapped in cotton is a programme to create awareness on child protection and child labour and create awareness on education in community level for those children who are working in cotton farms and discontinue their study and to provide life skill for those girls who are aged between (14-18), provide vocational training for those youth whom are unemployment and dropped their education.

2. Intervened Area and community :

Intervention is in two Blocks named Kukshi and Manawar of Dhar district in Madhya Pradesh and thecommunity belongs to Bhil and Bhilala tribes.

3. Goal and Objectives :

Goal :

- ✓ Prevention of children involved in cotton farming and allied sector and allied chain,
- ✓ Linkage of children to main stream education and skill build up program for tribal youths
- ✓ Capacity enhancement of child protection mechanism in the state to secure the security of the most vulnerable children in the district

Objectives :

- To reduce Prevent at risk children from labour in cotton farms in Kukshi and Manawar
- To continue education both boys and girls who are engage in economical activity
- To provide life skills and vocational /Technical skill training to the youth for viable livelihoods
- Linkage boys and girls to the existing government programme on skill development programme
- Establishing Child protection committee and children group in the villages for monitor and prevent child labour
- To conduct sensitization and awareness sessions on social protection schemes among the community in child labour and child rights

4. Activities

- Awareness and Mass education
- School admission Campaign programme
- Wall Painting for Creating learning enabling environment
- Organize skill development fairs/awareness drives/meetings to make adolescents aware on possible options of alternate employment
- Mobilization and Awareness Raised Activity
- Training and Capacity Building to SMC, SCG, SHG, CPC ACG
- Life skill training to Adolescent
- Research and Documentation
- Advocacy and networking District, Block and Panchayat level.
- Consultation meeting with line department.

5. Major Achievements and Impact

Achievement :

- 1131 children were free from Child labour and 1945 of Survivors and Risk Children Rehabilitated through linkage with School Education,
- 107 School children Group has formed in PS and MS in both the block govt. Primary and.
- 116 school completed wall painting for Creating learning enabling environment through developing child friendly/ attractive infrastructure in classroom to prevent dropout of survivors and at risk children
- 2 children's has received awarded from education minister who are enrolled 24 out of school children in school.
- 348 Survivors and at Risk Boys and Girls (15-20) youth vocationally trained and 115 has received Job in different Sctor1
- 260 Adolescent trained on Life skill
- 2970 House hold sensitized and mobilized according to the need of programme
- 4617 community members are initially mobilized on child rights and child protection
- 2269 HH has linked in Social Security Schemes.
- 3108 person has linked in Social Security Schemes.
- 1550 children's Adhar Corrected in this period
- 116 SMC members have received Training in this Period. And Covered 116 MS and PS
- 90 Government Officials from ICPS, SJPU, CWC, JJB, education, WCD and Labour department are sensitised about the child rights issues at village level and are adequately aware on Child Protection and Child rights.
- 122 women form the active SHGs have trained as women champions who will promote gender equality and equal wages, produce cotton without involvement of child labour.
- 80 SHGs are empowered to strengthen child rights.
- PUJA SHG has taken PDS shop with the initiative Trapped in Cotton Project staff. 581 HH and 3 village has been taking Commodities since August 2018

Impact :

- Women participation has increased
- Child labour in project areahas got reduced.
- Community awareness on education and child rights has increased.
- Women raised their voice and came out for decision making process.
- Adolescent has changed their life style after life skill training.
- Community based Groups have taken initiative for creating awareness on Child rights, Education, and Child marriage.
- Women are encouraging farmers to produce cotton without involvement of child labour

through SHGs.

- School children have raised their issues in front of different stakeholders.

6. Success Stories/ Case study :

6.1 STRUGGLEBY RANJANA

Ranjana Chouhan, 17 years old young girl from Dalit community in Mankarpura village belonging to a landless family, could not continu her study after 10+2 because her father drunk liquor every time and mother could not work and earn money due to sickness. She used to goto urban areas by pick-upvanto work for 20-25 days in a month and earn some money for her family needs. Whenever she felt sickness due to stomach problem or menstruation she was enforced to go to work because of poverty without any rest in her life. She felt bad touch by other male passengers who went in pick upvan for work to urban area. She was always discriminated in her village and outside the village in people's gathering like marriage party etc. because she belonged to Dalit community. She always analyzed her situation and wanted to come out of this pitiable situation.

She became member of adolescent children group, when MGSA started work and formed the children group in the villages to identifythe drop- out children from education, child labor and girls (between the age of 14-18) to provide them life skill training and vocational training for their self reliance. She contacted to the team leader andgot training under the vocational training program with the facilitation of MGSA. She got training in computer operating system and got a job in city. She used to travel 30 kmdaily for her job and spent much money on her travel. She shared her problems with the team member and then they discussed for other employmentfor her. At the end they agreed to provide her Photoshop training that she can start photographyshop at her own place where she could photocopy the documents and earn some money.

She along with her brother collected sands from nearby river and built bricks at home. Family members worked to build a small computer room. She took loan from SHG group formed under the project @2% interest rate and some personal loan from relatives to purchase old computer and printer. She provides photo and typing service to villagers. By and by, villagers and school children are becoming customers. She purchased stationery items when school children asked and requested her to keep some stationery. Now villagers from 7 villages have become her regular customers. Ranjna says with good smile that this shop uplifted her family from poverty and discrimination, now other villagers who came to her shop they sit with their family member and some time they ask for drinking water also. She earns Rs. 300-400 per day. She again continued her

education and passed her B.A first year. She is confident to do something new and innovative and provide education to her younger brother. Now, she has planned to open common service center at her shop under the government schemes in Digital India. She said "Becoming the member of group was turning point of my life where I met the MGSA staff and shared my story and they facilitated".

6.2 LEARNED AND EARNED : RANU

Miss Ranu belongs to ST & landless household in the village Bidpuraandused to work as daily labour for her family's food because her father could not work due to illnessas he was suffering from serious disease since 2011. She used to work along with her mother and 2 younger brothers for her family basic and daily needs as a result she discontinued her study. She used to go by Pick- Up van for labor in other's cotton farm. She used to work 25-30 days every month to earn @100 Rupees per day. Her family gets 24 kg of Maize and 4 kg wheat and rice per members @ 1 rupee per kg as having BPL card each month. Her younger brother and sister stopped their education and used to gofor labour work due to poverty.

Ranu and her brother borrowed 2 Bigha land for share cropping. Sometime Ranu also used to graze her goats and cowto manage her livestock. They collect NTFPs like Nimuli , Gum and do some cultivation of vegetables in the backyard of their house for alternative livelihood option.

She came in touch with the team member of the project and showed her willingness to join the vocational training. Slowly, she became part of all activities of the project organized at village and block level. She brought many children to the school for admission under "Go School Campaign'. She got vocational training in cloth stitching for self employment under this MGSA project.Shecompleted her training in many phases because she had to go in between to earn some money for her family through wages. Finally she got trained and purchased an old stitching machine within village. She opened a shop for stitching ladies garments such suit, salwar, blouse and petticoat. Initially she has started earning 2000-2500 rupees per month and herparents are very happy. She has decided to support her brother in his studies.

She says,"If these types of noble work by MGSA will continue in forthcoming years, so many young girls like her will be able to change their situation and become self reliant and can also help others."

11. BUILDING DOMESTIC RESOURCE MOBILIZATION CAPACITIES OF CSO'STHROUGH INNOVATION TECHNOLOGY & SOCIAL ENTERPRISE

1. BACKGROUND AND INTRODUCTION :

Opportunities before voluntary organizationsfor foreign funds have reducedbut in meanwhile crowd funding and CSR funding opportunities haveincreased in our country also. In this conjunction, WHH has been working for the capacity building of Civil Society Organizations (CSOs) on fund raising at local level through Mahatma Gandhi Seva Ashram. The purpose of this project is to develop the capacity of partner organizations for building domestic resource mobilization and empowerment of marginalized community. MGSA is working with 11 selected CSOs at national level.

2. GOAL AND OBJECTIVES :

- To contribute to a strengthened civil society in India that is able to perform its independent role of empowering vulnerable sections of Indian society.
- To enhance capacities of selected civil society organization on resource mobilization through creation of a common platform that brings together different resources and stakeholders.

Replace above points

(This intervention of MGSA aims at enhancing capacities of selected civil society organizations to mobilizes their own resources and thus become able to sustain themselves in their efforts to empower vulnerable communities.)

3. RESULTWISE ACTIVITIES :

Followings are the result wise activities in the project :

Result 1: A crowdfunding platform (ShareOn.in) established to raise funds for CSOs.

- ✓ Planning and Designing of web based crowdfunding platform.
- ✓ Develop and Launch the web-based platform.
- ✓ Identify, Select and Design support to promising campaigns.
- ✓ Build capacities of CSOs on Communications, IT tools and PR.
- ✓ Marketing plan for the crowdfunding platform.

Result 2 : Selected CSOs have successfully developed social enterprise models.

- ✓ Build Capacities of selected CSOs to make transition from non-profit to hybrid models.
- ✓ Select potential social business ideas and implement pilots.

Result 3 : Improved access to Institutional funds.

- ✓ Build capacities of network partners on fundraising related areas.OUTPUT INDICATOR OF THE PROJECT
- ✓ **Transformation :** 20 NGO/CSOs undergo organizational development process.
- ✓ **Social Enterprise :** 10 Social Enterprises formed (3 are led by women).
- ✓ **Employment :** 500 rural women get livelihood support through social enterprise.

4. ACTIVITIES COMPLETED

a. Baseline survey : Details information such as CSOs, its establishment, Mission, Vision, Human Resource, Organizational Structure, Projects & impact made, Funding Agencies, etc. were collected from 12 CSOs in a format for the project requirement and assessment.

b. Inception workshop for the team member : Inception workshopwasheld at WHH Delhi office during **1st week of July 2018**, in which**11 CSOs** came to know about the purpose of the project. After the inception workshop MGSA got **12 nomination forms** from **12 CSOs**(one of them, was briefed overphone call with presentation and minutes) that showed their interest in this project.

c. Review and Evaluation of the Project: With the objective of review and evaluation of activities executed in the first 6 months of project and scheduling and planning of activities for upcoming 6 month, MGSA team came together at WHH Delhi office on **7th of August 2018**. All activities in the first 6 months of this project were reviewed in planning and review meeting held at WHH Delhi office, along with tasks and activities outlined for the upcoming 6 months. After review and planning meeting work on communication database, communication baseline, first draft of

campaigns stories and mentoring phase werestarted.

d. **Workshop on communication and marketing needs of the CSOs**: Communication and marketing needs of CSOs were clarified at 1st communication workshop organized in Kolkata during **1st week of October 2018** in presence of an expert communication consultant agency **'Barapani'**. Here CSOs shared their compulsions and difficultiesstartingfrom Facebook page making to twitter handle creation and webpage revamp. Due to lack of communication and marketing strategy, the CSOs were unable to work according to theirfull capability and evenlacked access to funds and financial resources. After this workshop, under the guidance of Badapani, CSOs started working on their web pages, social media platforms and other mediums.

e. **Consultation cum workshop on Social Enterprise/ Hybrid Models :** Recent major activity of project was consultation cum workshop on social enterprise /hybrid models, held at Bhopal on **17th- 18th December 2018**. Objective of the workshop was to discuss and learn as to how CSOs will transform and lead to social enterprise and hybrid models. Here consultants made CSOs aware to the social enterprise/hybrid models. So far, MGSA received **confirmation** from 11 CSOs and **social enterprise plans** from 6 CSOs, along with 5 Campaign stories from 5 CSOs. This reflects how positive the CSOs are getting regarding the Social Enterprise Models/ Hybrid Models.

f. **Activities For "A Change":**

- **Campaign Designing:** Identified and supported CSOs in Campaign designing.
- **Campaign Story:** Initiated, motivated and supported CSOs to write Campaign stories.
- **Updating platforms:** Supported CSOs in changingand updating content on their respective websites.
- **Social Media Platforms:** Helped CSOs to get regular on Social media platforms, while explaining how important it is. Also, motivated many to get on multiple platforms.
- **Exposure with the experts:** Helped these CSOs towards experiential learning with the experienced crowd funding teams.
- **CSO led Social Enterprises:**Provided exposure to different crowdfunding platforms and ideas.

5. ACHIEVEMENT

- **Social Enterprise:** After these actions, one-on-one discussions, workshops and meetings, 11 Civil Society Organizations are all set to work on Social Enterprise

Models or Hybrid Models.

- **Proposals:** 6 Proposals along with the Social Enterprise ideas have been submitted by the CSOs.
- **Visit:** Visited 5 CSOs one by one for the on-field need assessment and to identify the scope of social enterprise / hybrid model.
- **Campaign stories:** Explored multiple places of ongoing activities (at CSO's location) during visits based on the CSOs need and demand, and supported them in designing campaign and writing stories. So far, 5 CSOs have submitted their campaign stories.

6. IMPACT

- The MGSA has been able to broaden the ideologies of some CSOs regarding Social Enterprise model / Hybrid Models.
- Increasehas been observed in public outreach of CSOs on community rights and natural resources.
- Changes are taking place in financial sustainability of social impact actions.
- A change can be seen on how highly active some CSOs are, on their websites and other social media platforms.

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महात्मा गांधी सेवा आश्रम को मिला राज्य स्तरीय सम्मान

चार दिवसीय बालिका दिवस पर सम्मानित हुए सचिव परमार व प्रबंधक जादौन

श्योपुर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिका दिवस का शुभारंभ किया गया चार दिवसीय इस आयोजन के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उपस्थित रहे जबकि अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री मति इमरती देवी ने की विशिष्ट अतिथि ग्वालियर विधायक मुन्ना लाल गोयल,जिला पंचायत अध्यक्ष , जिलाधीश अनुराग चौधरी रहे व मुख्य वक्ता दिल्ली से पधारी अंतर्राष्ट्रीय फेमिनिस्ट कमला भसीन उपस्थित रही

कार्यक्रम के प्रारम्भ में विभिन्न युद्धों में शहीद वीरों के परिवार जन को सम्मानित किया गया तदुपरांत महिला सशक्तीकरण एवं बाल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान हेतु खाद्य मंत्री तोमर व महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने अपने करकमलों से महात्मा गांधी सेवा आश्रम श्योपुर को शाल श्री फल एवं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया जिसे आश्रम के सचिव रनसिंह परमार एवं श्योपुर के आश्रम प्रबंधक जयसिंह जादौन ने संयुक्त रूप से ग्रहण किया श्री परमार ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरी टीम की है जो बधाई की पात्र है उन्होंने आगे कहाकि महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना 1970 में महान गांधीवादी डॉक्टर एसएन सुब्बाराव द्वारा चंबल घाटी में शांति एवं सद्भावना की स्थापना के लिए की थी, इसके पश्चात आश्रम ने पूरी चंबल घाटी में शांति और अहिंसा के साथ न्याय एवं समानता पर आधारित नए समाज की रचना के लिए काम शुरू किया । पिछले कुछ वर्षों में कुपोषण के दौर से गुजर रहे शोपुर जिले में कुपोषण मुक्त अभियान का प्रारंभ आश्रम द्वारा किया गया तथा पूरे जिले की 1227 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सहभागी सीख प्रक्रिया के माध्यम से कुपोषण से बचने का प्रशिक्षण दिया गया।

महात्मा गांधी सेवा आश्रम के प्रबंधक पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

सहभागी सीख प्रिक्रिया का फैलाव पूरे जिले में हुआ तथा 15 से 49 वर्ष की 80000 से अधिक महिलाओं तक पहुंचाया गया इन महिलाओं को कटोरी से बच्चों को खिलाना,गोद भराई ,अन्नप्रशन,सामुदायिक स्कोरकार्ड,सामुदायिक बैठकों के माध्यम से भोजन की उपलब्धता,भोजन की विविधता के साथ उपलब्ध प्राकृतिक संपदा को रोजाना के खानपान में शामिल करने का प्रशिक्षण दिया गया कुपोषण से मुक्ति के लिए संस्था ने 3200 पोषण बाड़ियों को तैयार किया गया जिससे हर परिवार को हरी सब्जियां एवं फल उपलब्ध हो सके बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सोपुर जिले की शिक्षा से वंचित 2700 बेटियों को पढ़ाओ अभियान से जुड़कर शिक्षा दिलाने का काम किया। बाल संरक्षण पर 1393 बच्चों को उनके अधिकार दिलाने का काम किया चाइल्डलाइन के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में 50000 से अधिक बच्चों को उनके अधिकार से जोड़ने का काम किया।

सहभागी सीख और क्रियांवयन को लेकर बैठक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

पलसूद @ पत्रिका. नगर के आंगनवाड़ी केंद्र 4 में बुधवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा वर्मा ने सहभागी सीख एवं क्रियांवयन की बैठक का आयोजन यूनिसेफ, एकजुट, एमजीएसए के सहयोग से किया। बैठक में मातृत्व एवं शिशु पोषण में सुधार के लिए समुदाय में असमानताओं को कदम के खेल के माध्यम से समझाया। साथ ही लकड़ी के खेल द्वारा एकता के बारे में जानकारी दी।

बैठक में पार्षद वनिता सेन, सरिता बाई, महात्मा गांधी सेवा आश्रम संस्था राजपुर के उदयराम ठाकुर, संतोष साखनेर पिरामल फाउंडेशन नीति आयोग पलसूद, पर्यवेक्षक माधिन्दा बंडोड़, कार्यकर्ता राधा राठौड़ सहित किशोरी और महिलाएं मौजूद थी।

Organic farming gains momentum in Assam

From Our Correspondent

DHEMAJI, July 03: Organic farming is gaining fast momentum in Assam with Ekta Parisahd again beginning another three-day training camp on organic farming and vermin compost making a at Moridham Shanti Sadhana Ashram here on Monday.

Three resource persons are conducting the training with practical demonstration for 53 local people, its coordinator Nayan Tara said.

This would undoubtedly supplement the efforts of Assam Govt to promote organic cultivation in the state with the help of global organic scientist Dr Nilamadhaba Nanda.

Interestingly, Dr Nada at the request of Chief Minister Sarbananda Sonowal has recently submitted a proposal to develop a biotechnology park by California-based Shree Biotech, in a place to be decided by the state Govt on PPP mode. The company's product – Win (Shree) Crops- an organic manure, has been doubling crop production and tripling pulse production in 40 nations and certified by numerous global scientific agencies and Assam Agricultural University.

गांधी सेवा आश्रम में मातृ-शिशु पोषण सशक्तिकरण सम्मेलन का हुआ आयोजन

सभी के समन्वय से मिलेगी जिले को कुपोषण से मुक्ति : कलेक्टर

हर बच्चा कुपोषण मुक्त हो, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे हम : रनसिंह

श्योपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

महात्मा गांधी सेवा आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रनसिंह परमार ने शनिवार को गांधी सेवा आश्रम कार्यालय पर खाद्य एवं पोषण विविधता कार्यक्रम के तहत काम कर रहे कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी गई। श्री परमार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिले का असल मकसद कुपोषण को मिटाना है। जब तक हर बच्चा कुपोषण मुक्त न हो जाए, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है।

बैठक में श्री परमार ने बताया कि हमने अभी तक 50 गांवों में पोषणवाड़ी लगाई है। इससे 2 हजार परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। पोषणवाड़ी में फलदार पौधे पपीता, नींबू, आम, आंवला, अमरूद, जामुन, कटहल के पेड़ लगाए गए हैं। इनमें से [illegible] फलदार पेड़ों में फल आने भी शुरू हो गए हैं। पोषणवाड़ी कुपोषण मिटाने में सहायक साबित होगी। इसके लिए द्वितीय चरण में पोषण बाड़ी के

बैठक में मौजूद गांधी सेवा आश्रम के पदाधिकारी व कार्यकर्ता।

महात्मा गांधी सेवा आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखे विचार

माध्यम से घर-घर में और सामुदायिक रूप से सब्जियां उगाने का काम कराया जाएगा। 7 हजार 840 परिवारों को पोषणबाड़ी लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 60 परिवारों को 20 जून तक चिह्नित कर लिया जाएगा। 60 हजार फलदार पौधे [illegible] वितरण के लिए मंगाई जा रही हैं। बैठक में संभागीय समन्वयक रामदत्त सिंह तोमर, जयसिंह जादौन, शबनम अफगानी, ज्योति सोलंकी, नीरज श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

छिंदवार के पंडो आदिवासी श्रमदान कर बना रहे स्टाप डेम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पोड़ीउपरोड़ा. विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पंचायत लाद के आश्रित ग्राम छिंदवार में जल संचय को लेकर तपती दोपहरी में ग्रामीण श्रमदान कर स्टॉप डेम का निर्माण कर रहे हैं।

इसमें कुल 42 परिवार पंडो जाति के लोग लगे हुए हैं। इसका भूमिपूजन जिला पंचायत सदस्य राय सिंह मरकाम व जिला पंचायत सदस्य किरण कुजुर द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच हिमांशु तंवर उपस्थिति में इस श्रमदान शिविर को गांव की मुखिया द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें शिव कुमार पंडो, बृज लाल पंडो, अमर सिंह, धनुराम पंडो, चैन साव पंडो, फुलेश्वरी बाई, प्यारो बाई, पुनोता बाई शामिल हैं। एकता परिषद जन संगठन के सहयोग से विगत कई वर्षों से जल संचय का कार्यक्रम अलग-अलग गांव में किया जा रहा है। एकता परिषद की ओर से रामसिंह उईके बृजलाल मार्को, इंदिरा यादव, कर्मपाल चौहान, निर्मला कुजुर व मुरली दास संत सहयोग कर रहे हैं।

स्टापडेम के लिए श्रमदान करते ग्रामीण।

Water conservation camp organised

■ Staff Reporter

EKTA parishad Shivpuri stared a five days water conservation camp at Shyampur village Badarvas Block Shivpuri District. In this camp 150 youth and villagers participating from 6 districts of Chambal region. This camp was inaugurated by Dr Ransingh Parmar, President of Ektaparishad in the presents Ramesh Sharma National Convener of Ektaparishad, Deepak agrawal state convener of Ektaparishad, Ramdat Tomar Convener of Ektaparishad Chambal region Ramprakash Sharma District convener of EKta parishad and village leaders of ektaparishad.

During the inauguration speech, Dr Pramar told that without making proper system to reserve rain water, we can't make sustainable solution for water issue in Chambal region. He also mentioned that this camp wills create a model for water conservation and people around Chambal will get inspiration to make peoples based model to compact water issue. Ramesh Sharma National convener of Ektaparishad told that this camp will open the eyes of state to make more participation of people during the planning and implementation process of water saving strategy of Government. Deepak Agrawal said that Ektaparishad Madhyapradesh is doing a campaign to save water in Madhya Pradesh through youth camps. Without involving youth and local people we can't find any sustainable solution for water crisis he added.

Water Conservation camp organised at Shivpuri district.

Ramprakah the district co-ordinator of EP said that they will create a pound which will have 300meeter length and 15 meter width and it will solve the water issue of 65 Saharia tribe families. In this camp village people are participating in a big way and they are also feeding the campers two times in a day. Ramdat Tomar said that this camp will conclude on May 10, Campers are doing 3hours Shramdhan (Manual work) every day from morning 6 am to 9am the rest of the time they will get the trainings on creating nonviolent way to solve their other social economical and political issue.

In urban areas Municipal Corporation has appealed to the public not to wash their cars for the next four months and to reuse and recycle water wherever and whenever possible.

पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक की लाद पंचायत में पानी का संकट...

श्रमदान कर डेम बना रहे पंडो की मदद करेंगे विधायक, कलेक्टर को भेजा पत्र

भाई जी के 91 वें जन्मदिवस समारोह की झलकियाँ

राष्ट्रीय युवा योजना एवं राजस्थान सरकार द्वारा डॉ. एस. एन. सुब्बराव (भाई जी) का 91वा जन्मदिवस समारोह राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलौत की अध्यक्षता में बिड़ला सभागार, जयपुर में 07 फरवरी 2019 को मनाया गया।